मनेन्द्रगढ़
04 जुलाई 2026 शनिवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

भारी बारिश के बाद हिमाचल में लैंडस्लाइड गाड़ियां दबीं , गुजरात में सड़कें डूबीं

भोपाल/ जयपुर/ लखनऊ/ पटना, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में गुरुवार रात भारी बारिश हुई। किन्नौर के चोलिंग में बारिश के बाद मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया। दो गाड़ियां दब गई। राज्य में 49 सड़कें बंद हैं। इधर, यूपी में शुक्रवार सुबह 3 बजे लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, जालौन समेत 5 शहरों में बारिश हुई। उन्नाव में पानी घरों में घुस गया। गुजरात के वलसाड में सड़कें पानी में डूब गई, गाड़ियां चलते-चलते बंद हो गई।

मध्य प्रदेश में मानसून 9 दिन में ही पूरे प्रदेश में छा गया। धार, बड़वानी, खरगोन और देवास में अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश का अनुमान है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से राम घाट के पास मंदिर डूब गए। वहीं मुंबई में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।

राजस्थान के जयपुर में 2 दिन से रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कोटा, बारां और झालावाड़ के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लगातार पत्थर गिरे थे। सुरक्षा के चलते केदारनाथ

यात्रा रोक दी गई थी।

मौसम विभाग के अनुसार, 5 जुलाई तक मानसून के पूरे देश को कवर करने की संभावना है, जबकि इसका सामान्य समय 8 जुलाई माना जाता है। यानी शुरुआती सुस्ती के बावजूद मानसून अपनी सामान्य प्रगति के करीब पहुंच गया है। हाल ही में मौसम विभाग ने बताया था कि अगले कुछ दिनों में

मानसून 3 दिन देरी से आया, 3 दिन पहले पूरे देश कवर करेगा... मानसून ने 1 जून की जगह 3 दिन लेट 4 जून को भारत में एंट्री ली थी। इस दौरान कई राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। बीच-बीच में 'ब्रेक मानसून' जैसी स्थिति बनने से यह आशंका जताई जाने लगी थी कि इस बार मानसून पूरे देश को सामान्य समय से देर से कवर करेगा। हालांकि, जुलाई की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र और अनुकूल परिस्थितियों के कारण मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली।

बदमाश ब्लूटूथ के जरिए बैटरी ऑफ कर देते थे इलेक्ट्रिक कार-स्कूटर को खतरा नहीं

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली समेत कई शहरों में ई-रिक्शा चालकों के लिए परेशानी बने 3 एप को सरकार ने एप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये एप BAT-BMS, लॉसिजी और इपोच ली-आयन हैं। आईटी मंत्रालय ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। हालांकि, ये एप प्ले स्टोर पर अब भी मौजूद हैं। हाल ही में शिकायतें मिली थीं कि कुछ लोग इन एप से ब्लूटूथ के जरिए ई-रिक्शा की बैटरी को बंद कर चलते ई-रिक्शा को रोक देते थे। इससे चालकों को काफी परेशानी हो रही थी। इन घटनाओं के वीडियो भी वायरल हुए। दरअसल, कुछ ई-रिक्शा की लीथियम बैटरियों का ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम बिना पासवर्ड या कमजोर सुरक्षा के था, इसलिए एप उससे कनेक्ट हो गया। हालांकि, कारों के बैटरी सिस्टम में मजबूत सुरक्षा और एन्क्रिप्शन होता है, इसलिए कोई सामान्य एप उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता।

: ब्रीफ बॉक्स :

पंजाब में 3 बच्चों की हत्या कर मां का सुसाइड

पहले खाने में जहर दिया, फिर गला घोंटा, उसके बाद खुद पंखे से लटक गई

मानसा,एजेंसी। पंजाब के मानसा में मां ने 3 बच्चों की हत्या कर खुद भी सुसाइड कर लिया। उसने पहले 2 बेटियों और एक बेटे को जहर दिया। वह जिंदा न बच सकें, इसके लिए उनका गला भी घोट दिया। इसके बाद खुद भी घर के कमरे में लगे फंदे से लटक गई। बच्चों के पिता की पहले मौत हो चुकी है। जिस वक्त उसने यह वारदात की, वह घर पर अकेली थी। उसकी सास रिश्तेदारी में गई हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत वहां पहुंची। जिसके बाद चारों डेडबॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाई। पुलिस इसकी वजह की जांच के लिए परिजनों के बयान दर्ज कर रही है।

किराए के कमरे में रहती, पति की मौत हो चुकी : पुलिस के मुताबिक संदीप कौर (35) मानसा के वार्ड नंबर 3 में गुरुद्वारे के पास किराए के कमरे में रहती थी। उसके 3 बच्चे कालो (12), मोटो (7)

पति ने 40 साल की इन्फ्लुएंसर की हत्या की

चाकू से गोदा, फिर खुद पर वार किए

मेरठ,एजेंसी। मेरठ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान (40) की शुक्रवार सुबह 6 बजे पति ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पति प्रदीप चौहान (42) ने खुद पर भी कई वार किए। वह बुरी तरह जख्मी हो गया। बच्चे चीखते-चिल्लाते बाहर आए। पड़ोसी अंदर पहुंचे तो फर्श पर निशा खून से लथपथ पड़ी थी। कुछ दूरी पर घायल प्रदीप भी तड़प रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर्स ने महिला इन्फ्लुएंसर को मृत घोषित कर दिया।

बेंगलुरु डे-केयर मामले में दो महिला अरेस्ट

बाथरूम में जेट से पानी डाला, वॉशिंग मशीन में बैठाया था

बेंगलुरु,एजेंसी। बेंगलुरु के डे-केयर सेंटर में बच्चों से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को विजयलक्ष्मी और मंजुला नाम की दो महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी वही महिलाएं हैं जो वायरल वीडियो में बच्चों को प्रताड़ित करती नजर आ रही थीं। यह मामला आईटी कंपनी कैपजेमिनी के एचएएल कैंपस स्थित डे-केयर सेंटर का है। बुधवार को वायरल वीडियो में बच्चों को टॉयलेट में बंद कर दिया गया था। चेहरे पर जेट स्प्रे से पानी डाला गया और वॉशिंग मशीन में बिठाया गया था। मामले में पुलिस ने पहले पांच महिला केयरगिवर्स के खिलाफ केस दर्ज किया था। सोशल मीडिया पर

पैरेंट्स के कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक पैरेंट्स ने लिखा- काश ये,ढ्व वीडियो होता, यकीन नहीं हो रहा बच्चों के साथ ऐसा किया गया।

पैरेंट्स बोले- काश ये वीडियो एआई वाला होता: जिन बच्चों के साथ डे-केयर में बदसलूकी की गई है। उनके पैरेंट्स फिलहाल सामने नहीं आए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर अन्य पैरेंट्स रिएक्शन दे रहे हैं। एक मां ने फेसबुक पर लिखा कि, 'काश यह AI से बना हुआ वीडियो होता, असली नहीं। यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है।

कंपनी ने डे-केयर सेंटर बंद किया... कैपजेमिनी ने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। एहतियात के तौर पर बेंगलुरु स्थित ऑन-कैंपस डे-केयर सेंटर को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

राजस्थान-20 से ज्यादा शहरों में एटीएस के छापे, एक गिरफ्तार

● 28 हिरासत में, पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से कनेक्शन की आशंका

जयपुर,एजेंसी। एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की टीमों ने शुक्रवार सुबह राजस्थान के 20 से ज्यादा शहरों में छापेमारी की है। रेड पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए की गई है।

छापेमारी में 28 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बाड़मेर से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। एटीएस का दावा है कि भट्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन गेम, पैसों और गैंगस्टर ग्लैमर का लालच देकर युवाओं से दोस्ती करता है।

फिर उनसे संवेदनशील जगहों की फोटो मंगवाता है। भट्टी के चंगुल में ज्यादातर भारत-

पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों के युवा फंस रहे हैं।

जयपुर में भी छापेमारी, 20 साल का युवक गिरफ्तार: जानकारी के अनुसार एटीएस ने राजधानी में भी अलग-अलग एरिया में छापेमारी की है। जयपुर से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, बाड़मेर के गागरिया गांव से हिरासत में लिए गए बशीर (20) पुत्र आमद खान को हिरासत में लिया था।

रामसर थाने में पूछताछ के बाद एटीएस की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि बशीर शहजाद भट्टी से लगतार संपर्क में था।

भट्टी को फॉलो करने वाले रडार पर: सूत्रों के अनुसार लंबे समय से एटीएस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भट्टी को फॉलो करने वालों पर नजर रख रही है। शुक्रवार को हुई छापेमारी में ऐसे ही संदिग्धों को हिरासत में लेने की जानकारी है। इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट व दूसरी ऑनालाइन एक्विटविटी की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार भट्टी का नेटवर्क राजस्थान के साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी में भी है।

राजस्थान में भट्टी के स्लीपर सेल एक्टिव होने की आशंका... बीते करीब छह महीने से सुरक्ष एजेंसियां राजस्थान में शहजाद भट्टी के नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही हैं।

दावा:तीसरे शख्स को केतन के मर्डर की प्लानिंग पता थी

आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल देख हत्या का तरीका सीखा

पुणे,एजेंसी। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने बीड से एक युवक को हिरासत में लिया है। यह युवक बालेवाड़ी की एक कंपनी में काम करता है। दावा है कि तीसरा शख्स सिया या केतन में किसी एक का दोस्त है। दोनों ने उससे केतन के मर्डर की प्लानिंग शेयर की थी। हालांकि युवक का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस युवक को गवाह भी बना सकती है। वहीं, पुलिस सूत्रों के हवाले से जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी चेतन चौधरी और सिया ने वारदात से पहले टीवी सीरियल 'क्राइम पेट्रोल' के कई एपिसोड देखकर समझने की कोशिश की थी कि हत्या के बाद जांच एजेंसियों को कैसे चकमा दिया जा सकता है। 18 जून को लोहगढ़ किले से गिरकर 25 साल के केतन अग्रवाल की मौत हो गई थी। पुलिस का मानना है कि केतन, सिया और चेतन के रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसकी हत्या की साजिश रची गई।

सिया के साथ क्राइम सीन रीक्रिएशन: पुणे पुलिस ने गुरुवार को सिया गोयल के घर से घटना के दिन पहने गए कपड़े और कई डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। पुलिस सिया को लेकर पुणे के लुल्लानगर इलाके में ले गई। यहां स्थित एक पहाड़ी पर सिया और चेतन ने केतन अग्रवाल को गिराने की रिहर्सल की थी।

अमरनाथ यात्रा शुरू — पहले दिन 9 हजार श्रद्धालु दर्शन करेंगे, हर 2किमी. पर ऑक्सीजन बूथ

बालटाल रूट पर 12 जगह वाटरप्रूफ डोम बनाए

जम्मू,एजेंसी। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा शुक्रवार से शुरू हो गई। यात्रा का पहला जत्था गांदरबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के पहलगाम (नुनवान) बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 4,822 श्रद्धालु शामिल हैं। ये सभी श्रद्धालु गुरुवार को बेस कैंप में पहुंचे थे। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के मुताबिक, पहले जत्थे के श्रद्धालुओं के साथ जवान और अन्य व्यवस्थाओं में

लगे इतने ही लोग यानी 9 हजार लोग आज शाम तक दर्शन करेंगे।

यात्रा मार्ग पर हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ बनाए गए हैं। दोमेल रूट पर चार जगह बड़ी स्क्रीन के जरिए मौसम की जानकारी दी जा रही है। बालटाल रूट पर 12 जगह वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं।

अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान-पहलगाम से है। दूसरा रास्ता गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे बालटाल से है। यात्रा 28 अगस्त को खत्म होगी।

दोनों रूट पर 100-100 बेड के अस्पताल... दोनों यात्रा मार्गों पर एक हजार डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं। दोनों जगह 100-100 बेड के अत्याधुनिक अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं।

● **बालटाल (गांदरबल) :** यात्रा करते वक्त तबीयत बिगड़ती है तो सबसे पहले डोमेल गेट के पास ही 'मेडिकल एड सेंटर' है। फिर रेलपथरी पर इमरजेंसी मेडिकल सहायता केंद्र है। बरारी पर मेडिकल कैंप और ऑक्सीजन मिल जाएगी। फिर संगम टॉप पर आपातकालीन चिकित्सा केंद्र है।

● **नुनवान (पहलगाम) :** नुनवान बेस कैंप पर बड़ा मेडिकल अस्पताल है। चंदनवाड़ी में 100 बिस्तर का मुख्य बेस अस्पताल बनाया गया है। चढ़ाई से पहले यहां जांच करा सकते हैं।

राजा मर्डर-सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट बोला:टाइपिंग की गलती को बनाया आधार, रिहाई न हुई होती तो बेल रद्द कर देते

इंदौर/नई दिल्ली,एजेंसी। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- हमें हाईकोर्ट के फैसले पर कुछ आपत्तियां हैं लेकिन सोनम जेल से बाहर आ चुकी है, इसलिए हम उसकी जमानत पर रोक नहीं लगाएंगे।

इसके साथ ही कोर्ट ने मेघालय सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है,

जिसमें हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की।

इस दौरान मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- यह सुनियोजित हत्या का मामला है। सोनम ने 4 साथियों के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की, फिर शव को खाई में फेंक दिया था। घटना के बाद वह भाग निकली, बाद में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार की गई।

देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल है विक्रम-1, जल्द लॉन्चिंग संभव

स्काईरूट फाउंडर पवन बोले- अंतरिक्ष तक तेजी से पहुंचने वाला एआई-6जी, स्पेस इकोनॉमी में आगे होगा

हैदराबाद,एजेंसी। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1' अब लॉन्च के लिए तैयार है। स्काईरूट एयरोस्पेस ने इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए 12 जुलाई से 4 अगस्त तक की लॉन्च विंडो घोषित की है। यह भारत की प्राइवेट स्पेस क्षमता की पहली बड़ी परीक्षा है। इसकी सफलता से छोटे उपग्रहों को जरूरत के मुताबिक और ज्यादा तेजी से अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा।

इससे खेती, संचार, नेविगेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी सेवाएं और मजबूत होंगी। अगर विक्रम-1 सफल रहता है तो भारत निजी क्षेत्र के दम पर ऑर्बिट तक पहुंचने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा।

स्पेस से पूरी हो रहीं रोजमर्रा की जरूरतें: अगर आप फोन पर मैप्स चलाते हैं या डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो उसके पीछे भी अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट काम कर रहे होते हैं। मैप्स आपकी सटीक लोकेशन सैटेलाइट से मिले नेविगेशन सिग्नल के आधार पर बताते हैं, जबकि यूपीआई जैसी सेवाएं इंटरनेट और संचार नेटवर्क पर चलती हैं, जिन्हें दूरदराज के इलाकों में सैटेलाइट भी मजबूती देते हैं।

सैटेलाइट बढ़ेंगे तो हर क्षेत्र में सुविधाएं भी बढ़ेंगी: अंतरिक्ष में बढ़ते सैटेलाइट नेटवर्क के साथ लॉन्च की मांग भी कई गुना बढ़ेगी। अभी भारत में ज्यादातर सैटेलाइट इसरो लॉन्च करता है। लेकिन आने वाले सालों में सैटेलाइट की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में इसरो चंद्रयान, गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन जैसे बड़े मिशनों पर ध्यान देगा। स्काईरूट जैसी निजी कंपनियां छोटे सैटेलाइट को बार-बार और जरूरत के मुताबिक कक्षा में पहुंचाने का काम करेंगी। इससे मौसम, इंटरनेट, खेती, आपदा प्रबंधन और संचार जैसी सेवाएं पहले से ज्यादा तेज और सटीक हो सकेंगी।

स्पेसएक्स से अलग, 'कैब मॉडल' पर स्काईरूट... स्काईरूट की तुलना स्पेसएक्स से होती है, लेकिन दोनों का मॉडल अलग है। इसे ट्रेन और कैब से समझ सकते हैं। ट्रेन तय समय पर तय स्टेशन तक ही ले जाती है। लेकिन अगर आपको किसी खास समय पर किसी खास जगह पहुंचना हो, तो कैब बेहतर विकल्प है।

दिल्ली में बनेगा पहला अंडरग्राउंड सीबीआरएन कमांड सेंटर, युद्ध जैसे संकट में मिलेगी सुरक्षा, टेंडर जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। वैश्विक स्तर पर कई देशों के बीच टकराव को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी को पूरी तरह से सुरक्षित करने की तैयारी शुरू हो गई है। परमाणु या अन्य रासायनिक हमले से निपटने के लिए पहली बार यहां एक भूमिगत कमांड सेंटर बनाने की योजना तैयार हो गई है। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के नए मुख्यालय में ही यह कमांड सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें पांच साल का समय लग सकता है। यह दिल्ली का अपना भूमिगत केमिकल, बायोलाजिकल, रेडियोलाजिकल और न्यूक्लियर (सीबीआरएन) कमांड सेंटर होगा। इस कमांड सेंटर से परमाणु या रासायनिक आपदाओं और बड़े पैमाने पर आने वाले संकटों से निपटने में राजधानी की तैयारियों को मजबूती मिलेगी। यह नया कमांड सेंटर दिल्ली फायर सर्विसेज के बड़े आधुनिकीकरण रोडमैप का एक हिस्सा है।

टेंडर जारी कर दिया गया: डीएफएस के सूत्रों के मुताबिक, नए मुख्यालय के साथ इस कमांड सेंटर को तैयार करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

यह प्रस्तावित मुख्यालय एक प्लग-एंड-प्ले अंडरग्राउंड सीबीआरएन कमांड सेंटर से लैस होगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह परमाणु युद्ध, रेडियोलाजिकल लीक या खतरनाक रासायनिक आपदाओं के दौरान भी बिना किसी रुकावट के पूरी तरह चालू रहेगा।

साथ ही बाहर फैले खतरनाक रेडिएशन का अंदर मौजूद कर्मियों पर कोई असर नहीं होने देगा। इससे बेहद नाजुक और गंभीर परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कमांड और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बनाए रखा जा सकेगा।

डीएफएस मुख्यालय की जमीन पर ही बनाया जाएगा

फायर अधिकारी ने बताया कि किसी भी आपदा के समय यह मेन कमांड सेंटर दिल्ली में पहले से नेहरू प्लेस, लक्ष्मी नगर और रोहिणी में मौजूद तीनों आपदा केंद्रों के साथ मिलकर आपरेशंस को कॉर्डिनेट करेगा। इसके साथ ही, यह सेंटर राहत व बचाव कार्य करने वाली बटालियन का भी मार्गदर्शन करेगा। यह पूरा प्रोजेक्ट मौजूदा डीएफएस मुख्यालय की जमीन पर ही बनाया जाएगा। एक अधिकारी का कहना है कि किसी भी बड़ी आपदा, आगजनी या बचाव अभियान में दमकल विभाग अपनी भूमिका निभाता है। ऐसे में इस कमांड सेंटर का बनना दिल्ली के लिए बेहद जरूरी कदम है। इससे न केवल हाई-रिस्क परिस्थितियों में सभी संबंधित एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा, बल्कि घटना पर एक्शन लेने का रिस्पांस टाइम भी काफी कम हो जाएगा।

कमांड सेंटर से जुड़ी खास बातें सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर

अगले एक साल में एक मुख्य केंद्र बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएस और जीआइएस आधारित प्रणालियों से लैस होगा ताकि लाइव मानिटरिंग की जा सके।

जोनल कमांड सेंटर्स: दिल्ली के सभी पांच आपरेशनल जोन में अलग-अलग कमांड सेंटर भी बनाए जाएंगे।

25 साल का लांग-टर्म प्लान: यह पूरा प्रोजेक्ट डीएफएस के 25 साल के लांग-टर्म एक्शन प्लान का हिस्सा है। इसे तत्काल, मध्यम और दीर्घकालिक चरणों में बांटा गया है, ताकि बढ़ती आबादी और आपदा प्रबंधन की जरूरतों के हिसाब से दिल्ली के बुनियादी ढांचे, मैनपावर और तकनीकी क्षमताओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड किया जा सके।

बारिश में गीले हो गए स्कूल के जूते तो छात्रा ने पहने रबर के शूज, 6 घंटे अलग बिठाए रखा

कोलकाता, एजेंसी। इस हफ्ते कोलकाता में हुई दो अलग-अलग घटनाओं ने नियम बनाम सख्ती पर बहस छेड़ दी और अनुशासन के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना में बारिश में स्कूल के जूते भीगने के बाद रबर के जूते पहनकर आने पर एक बच्ची को कथित तौर पर छह घंटे तक अलग-थलग रखा गया। वहीं, 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। उसने बहुत गर्म चाय पी ली थी और इलाज के लिए चार घंटे तक इंतजार करना पड़ा।

ड्रेस कोड को लेकर छिड़ी बहस: जब माता-पिता, शिक्षकों और बाल मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अपनी राय रखी तो एक आम सवाल सामने आया कि क्या स्कूल बच्चों का चरित्र गढ़ रहे हैं या बस किसी भी कीमत पर नियमों का पालन कर रहे हैं? कोलकाता के एक डॉक्टर ने बताया कि जब उनकी बेटी क्लास में रबर के जूते पहनकर गई तो क्या हुआ। इसके बाद ड्रेस कोड को लेकर बहस छिड़ गई। उन्होंने पोस्ट किया, 'कल हुई भारी बारिश में मेरी छोटी बेटी के स्कूल के जूते भीग गए थे। आज वह पूरी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल गई, बस गीले जूतों की जगह उसने रबर के जूते पहने थे।' उनके अनुसार, जब स्कूल से फोन आया कि उनकी बेटी को क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि उसने तय किए गए जूते नहीं पहने थे तब माता-पिता दोनों अपने-अपने अस्पतालों में थे। उन्होंने गुजारिश की कि उसे एक दिन के लिए क्लास में आने दिया जाए और वादा किया कि वे दूसरे जूते का इंतजाम कर लेंगे। उन्होंने लिखा, 'किस प्रोटोकॉल और पढ़ाने के तरीके के किस हिस्से में उन्होंने किसी स्टूडेंट को उसके कपड़े अधूरे होने पर मना करना सीखा? एक टीचर के तौर पर यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। एक बच्चे ने अभी-अभी सीखा है कि किसी सजावट की अनजाने में हुई कमी, एक जिज्ञासु आत्मा से ज्यादा कीमती है।'

दूसरा मामला क्या है: इसी तरह मंगलवार को नरेंद्रपुर के रामकृष्ण मिशन विद्यालय में दीप्तांशु महतो की मौत के बाद से ही इस मामले पर बहस गरमा गई थी। एक अभिभावक ने कहा, 'मुझे हैरानी हुई कि लड़के की हालत बहुत गंभीर होने के बावजूद उसे अस्पताल तभी ले जाया गया जब उसके पिता वहां पहुंचे।' इसके अलावा, छात्रों के एक समूह ने कैंपस में अपने साथ हुई मारपीट के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि स्कूल से निकाले जाने के डर से वे पहले कभी अपनी बात नहीं कह पाए थे। ग्यारहवीं कक्षा के एक छात्र ने कहा, 'हममें से कई छात्रों को हॉस्टल में अलग-अलग तरह की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। तीन साल पहले इसी प्रताड़ना के कारण एक छात्र हॉस्टल से भाग गया था लेकिन मामले की जांच करने के बजाय उसे स्कूल से निकाल दिया गया।' पूर्व प्रिंसिपलों और शिक्षकों ने कहा कि अनुशासन और नियमों को कभी भी हद से ज्यादा सख्ती में नहीं बदलना चाहिए। साथ ही उन्होंने सिर्फ एक घटना के आधार पर रामकृष्ण मिशन के सभी स्कूलों को आंकने के खिलाफ भी आगाह किया। मॉडर्न हाई स्कूल की डायरेक्टर देवी कर ने कहा कि सख्ती कभी भी डर में नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'एक शिक्षक का मकसद बच्चे को सही रास्ते पर लाना होता है और यह बहुत ज्यादा सख्ती से हासिल नहीं किया जा सकता।

आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में भीषण हादसा, ट्रक-ऑटो की टक्कर में चार लोगों की मौत

मार्कापुरम, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। अमरावती-अनंतपुर राजमार्ग पर कंभम के पास एक लॉरी ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों की पहचान अवुला अलकनंदा (19), अवुला अंकलु (20), अवुला नागेश (17) और अवुला नागेश्वरी (2) के तौर पर की है। ये सभी गिद्दलूर के नल्लाबंडा बाजार के रहने वाले थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में घायल लोगों का इलाज कम्भम सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, यह हादसा लॉरी ड्राइवर के तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। गिद्दलूर के नल्लाबंदा बाजार के अवुला वीरक्का की शादी शुक्रवार सुबह 9:30 बजे कंभम की पामुलेटी से होनी थी। शादी से पहले बारात विनायक मंदिर में रुकी और नारियल फोड़कर दुल्हन की पूजा-अर्चना की। उसी दौरान, सामने से आ रहे एक ट्रक का नियंत्रण बिगड़ गया और उसने ऑटो और उसमें सवार लोगों को कुचल दिया।

क्रूज पर फैला नोरोवायरस, चालक दल समेत 125 लोग बीमार कितना खतरनाक है यह संक्रमण

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से कनाडा और अलास्का की यात्रा पर निकले एक लग्जरी क्रूज जहाज में नोरोवायरस का बड़ा प्रकोप सामने आया है। इस संक्रमण की चपेट में 125 लोग आए हैं, जिनमें 102 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य शामिल हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आखिर यह वायरस कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, जानिए इस एक्सप्लेनर में। सैन फ्रांसिस्को से रवाना होकर कनाडा और अलास्का की 20 दिन की यात्रा पर निकले रूबी प्रिंसेस क्रूज में नोरोवायरस संक्रमण फैलने से

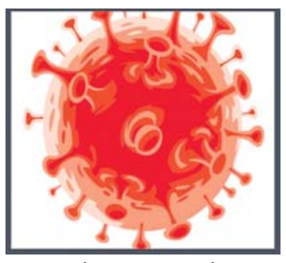

125 लोग बीमार हो गए। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, संक्रमितों में 102 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य शामिल हैं। घटना के बाद जहाज के सैन फ्रांसिस्को लौटते ही विशेष सफाई और संक्रमण नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि नोरोवायरस बंद जगहों और भीड़भाड़ वाले वातावरण में बहुत तेजी से फैलता है।

नोरोवायरस क्या है और यह इतना तेजी से क्यों फैलता है: नोरोवायरस पेट और आंत से जुड़ा अत्यधिक संक्रामक वायरस है। यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, दूषित भोजन या पानी पीने और संक्रमित सतहों को छूने से फैल सकता है।

क्रूज जहाज, हॉस्टल, अस्पताल और वृद्धाश्रम जैसी जगहों पर इसके फैलने का खतरा अधिक रहता है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग सीमित जगह में रहते हैं। अधिकांश लोगों में यह संक्रमण कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है।

इस मामले में कितने लोग प्रभावित हुए और कंपनी ने क्या कदम उठाए: सीडीसी के अनुसार, रूबी प्रिंसेस क्रूज पर कुल 3,032 यात्री और 1,144 चालक दल के सदस्य मौजूद थे। संक्रमण की जानकारी 28 जून को स्वास्थ्य अधिकारियों को दी गई। हालांकि सभी संक्रमित एक साथ बीमार नहीं हुए थे। प्रिंसेस क्रूज कंपनी ने कहा कि मामले सामने आते ही जहाज पर अतिरिक्त स्वच्छता अभियान चलाया गया। जहाज को अगली यात्रा से पहले पूरी तरह साफ और कीटाणुरहित किया गया ताकि संक्रमण दोबारा न फैले।

इंदौर में लव जिहाद: हिंदू बनकर मोहम्मद राहुल ने किया गायिका से दुष्कर्म, सिलीगुड़ी से बचकर मप्र पहुंची पीड़िता

इंदौर, एजेंसी। धार्मिक पहचान छुपाकर गायिका के साथ दुष्कर्म करने वाले मुस्लिम युवक को बाणगंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने अपना नाम राहुल बताकर युवती से दोस्ती की और बातचीत के बहाने कमरे पर ले गया। वहां जबरन संबंध बनाए, विरोध करने पर मांग पर सिंदूर भर दिया और कहने लगा आज से वह उसका पति हो गया। बाणगंगा थाने के टीआइ सियारामसिंह गुर्जर के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम अगस्त 2024 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ। पीड़िता वहां एक इवेंट के लिए गई थी। बाद में जब उसे पता चला कि राहुल मुस्लिम है, उसका पूरा नाम मोहम्मद राहुल पुत्र अब्दुल शेख है और उसके कई लड़कियों से संबंध हैं तो विरोध जताया। आरोपित ने युवती को कमरे में कैद कर लिया और मारपीट करने लगा। अक्टूबर 2025 में पीड़िता किसी तरह उसके चंगुल से निकली और दिल्ली में रहने वाली सहेली के पास पहुंची। वहां उसने बच्चे को जन्म दिया। इस साल मार्च में पीड़िता इंदौर में बेटे को लेकर मां के साथ रहने लगी। आरोपित उससे मिलने के बहाने इंदौर पहुंचा और पुनः संबंध बनाए।

रफीक के माध्यम से भारत में जासूसों तक पैसे पहुंचा रही थी पाकिस्तान की ISI, बैंक खातों से टेरर फंडिंग का पर्दाफाश

जयपुर, एजेंसी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किए गए 41वर्षीय रफीक चांद शेख के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राजस्थान सीआईडी की जांच में सामने आया कि रफीक पिछले चार साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी गतिविधियों में शामिल लोगों तक पैसे पहुंचाता था। यह पैसा आईएसआई रफीक तक पहुंचाती थी। इस साल जनवरी में जैसलमेर निवासी झाबराराम और असम के डिब्रूगढ़ वायुसेना स्टेशन पर एमटीएस पद पर तैनात सुमित कुमार को गिरफ्तार करने के बाद हुई पूछताछ में रफीक का नाम सामने आया। झाबराराम और सुमित ने महत्वपूर्ण जानकारियां आईएसआई तक पहुंचाई थी, जिसके बदले उन्हें रफीक ने पैसे दिए थे। सूत्रों के अनुसार, जांच में सामने आया कि पाकिस्तानी हैंडलर्स ने झाबराराम को जैसलमेर के संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी भेजने का काम सौंपा था। वह सेना के मूवमेंट, हथियारों एवं सैन्य ठिकानों की जानकारी इंटरनेट मीडिया के जरिये पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था, जिसके बदले पाकिस्तानी हैंडलर्स रफीक के माध्यम से पैसा पहुंचाते थे। सूत्रों के अनुसार, अब सीआईडी रफीक के पास मिले फर्जी बैंक खातों और झाबराराम के बैंक स्टेटमेंट का मिलान कर रही है।

अन्ना हजारे की धमकी के बाद पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार, नए आरटीआई नियमों पर रोक लगाने का दिया आदेश

मुंबई, एजेंसी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नए सूचना का अधिकार (आरटीआइ) नियमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि हाल ही में अधिसूचित संशोधित आरटीआइ नियमों को फिलहाल लागू न किया जाए। इन प्रस्तावित बदलावों में आरटीआई आवेदन शुल्क बढ़ाने, पहचान प्रमाण अनिवार्य करने और प्रत्येक आवेदन में केवल एक ही विषय से संबंधित जानकारी मांगने जैसी शर्तें शामिल थीं, जिन पर व्यापक विरोध हुआ था। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग को पत्र लिखकर कहा कि बिना अन्ना हजारे से विस्तृत चर्चा किए इन संशोधनों को लागू करना उचित नहीं होगा। इसके बाद राज्य सूचना आयोग ने भी संशोधित नियमों पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इससे पहले मुख्य सूचना आयुक्त ने अहमदनगर जिले

के रालेगण सिद्धि जाकर अन्ना हजारे से मुलाकात की थी और उन्हें प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अन्ना हजारे अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि ये संशोधन सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना को कमजोर करते हैं और आम नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करना कठिन बना देंगे। अन्ना हजारे ने चेतावनी दी थी कि यदि 'महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026' को वापस नहीं लिया गया, तो वे पांच जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। सरकार के फैसले को फिलहाल विरोध शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से एक बिल पास किया। इसका उद्देश्य महिला किसानों को मान्यता देना, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, संस्थागत लोन, खेती से जुड़ी सेवाओं और महिला किसान पहचान-पत्रों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा तैयार करना है। महिला किसान सशक्तीकरण बिल देश में इस तरह का पहला प्रस्तावित कानून है। इसका मकसद खेती में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। इसके लिए खेती से जुड़ी महिलाओं की मदद के लिए एक खास फंड बनाया जाएगा और अकेले खेती करने वाली महिलाओं को विशेष सहायता दी जाएगी। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि बिल में बताया गया है कि बुवाई से लेकर कटाई तक पुरुषों के साथ काम करने और डेरी फार्मिंग व पशुपालन जैसी सहायक गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद महिलाएं ज्यादातर संस्थागत लाभों से वंचित रही हैं, क्योंकि खेती की जमीन आमतौर पर परिवार के पुरुष सदस्यों के नाम पर होती है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की दो टूक, कहा- आतंकवादी सिर्फ आतंकी होता है

संयुक्त, एजेंसी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटना विश्व समुदाय के सामूहिक प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। भारत ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से आतंकवाद को उचित ठहराने के लिए किसी भी शिकायत को आधार बनाए बिना इस 'हत्यारी विचारधारा' को जड़ से मिटाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया व कहा, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही होता है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा, भारत सीमा पार आतंकवाद का दशकों से शिकार रहा है।

हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। कई जानें गईं, परिवार बर्बाद हुए। इसी अनुभव से भारत का रुख बना कि आतंकवाद को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा, चाहे कोई भी शिकायत, राजनीतिक उद्देश्य या रणनीतिक गुणाभाग हो, आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की बिना किसी हिचकिचाहट निंदा की जानी चाहिए। सदस्य देशों को इस संबंध में पूरा सहयोग करना चाहिए।

दोहरे मानदंड खारिज करना चाहिए: पर्वतनेनी ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंक-रोधी रणनीति (जीसीटीएस) की नौवीं समीक्षा को स्वीकार किए जाने के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद से निपटने को लेकर दोहरे मानदंडों को खारिज करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों, उनकी साजिश रचने वालों, उन्हें वित्तीय मदद देने वालों और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराना तथा न्याय के कठघरे में लाना जरूरी है।

आतंक-रोधी प्रयासों को कमजोर न होने दें: रीश ने कहा, आतंक-रोधी प्रयासों को गलत तुलना या राजनीतिक रंग वाले विमर्श के कारण कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, लगभग तीन दशक की देरी ने आतंकवाद से निपटने के हमारे सामूहिक प्रयासों में बाधा डाली है। अब सीसीआईटी को अंतिम रूप देने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने का समय आ गया है।

एफएटीएफ के मानकों का क्रियान्वयन मजबूत करें: यूएन में भारत के राजदूत ने कहा, हमें आतंक फैलाने में मददगार परिस्थितियों से निपटना चाहिए लेकिन हमें कभी भी परिस्थितियों को आतंकवाद के औचित्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें मानवाधिकारों और कानून के शासन को कायम रखना चाहिए लेकिन यह भी स्वीकार करना चाहिए कि पहला मानवाधिकार जीवन का अधिकार है और आतंकवाद इस मानवाधिकार पर सबसे प्रत्यक्ष हमला है। वह बोले, विश्व बिरादरी को वित्तीय खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के मानकों के क्रियान्वयन को मजबूत करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी क्षेत्र आतंकवाद के वित्तपोषण का सुरक्षित माध्यम न बने।

उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग

भारत ने कहा कि आतंकियों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग करने पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। यह निराशाजनक है कि जीसीटीएस की इस समीक्षा में आतंकियों को उनके नापाक कृत्यों के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी साधनों से वंचित रखने पर आम सहमति नहीं बन पाई।भारत ने कहा, उसने आतंक-रोधी वैश्विक प्रयासों में लगातार योगदान दिया है और आतंकी उद्देश्यों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से निपटने संबंधी दिल्ली घोषणा तथा 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलनों सहित कई अंतरराष्ट्रीय चर्चाएं की हैं।

खामेनेई के जनाजे में शामिल नहीं होंगे मोजतबा, धमकियों के बीच क्यों बदली गई रणनीति

तेहरान, एजेंसी। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनाजे की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अपने पिता के जनाजे में सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं होंगे। इसकी वजह सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताओं को बताया गया है। ईरान के भारत स्थित प्रतिनिधि आयतुल्ला हाकिम इलाही ने कहा कि इस्राइल से संभावित खतरे और निगरानी के जोखिम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

क्या सुरक्षा खतरे के कारण लिया गया यह फैसला: आयतुल्ला हाकिम इलाही के मुताबिक, मौजूदा हालात में सार्वजनिक कार्यक्रम में मोजतबा खामेनेई की मौजूदगी सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरी मानी गई। उनका कहना है कि इस्राइल की

ओर से संभावित हमले या निगरानी की आशंका को देखते हुए अंतिम संस्कार में उनकी उपस्थिति टालने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, अली खामेनेई का जनाजा चार जुलाई से नौ जुलाई के बीच ईरान और इराक के विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी जाएगी।

ईरान ने अमेरिका और इस्राइल को क्या चेतावनी दी: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस्राइल को नियंत्रित करें। उन्होंने कहा कि यदि ईरान के नेतृत्व या जनता को किसी तरह की धमकी दी गई तो उसका तत्काल और शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा। अराघची का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें इस्राइल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने कथित तौर पर मोजतबा खामेनेई को निशाना बनाए जाने जैसी टिप्पणी की थी। ईरान ने इसे गंभीर सुरक्षा चुनौती माना है।

क्या पश्चिम एशिया में कूटनीतिक कोशिशें भी जारी: तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। हाल ही में कतर और पाकिस्तान ने दोहा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों में 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति होने की बात कही गई।

मऊगंज में स्कॉर्पियो से शराब सप्लाई का आरोप, वीडियो वायरल; नशा मुक्ति अभियान पर उठे सवाल

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवैध शराब सप्लाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक स्कॉर्पियो वाहन से ग्रामीण क्षेत्रों में पैकारी के लिए शराब लोड करते हुए दृश्य दिखाई दे रहे हैं हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है वीडियो सामने आने के बाद जिले में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान और अवैध शराब के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अभियानों के बावजूद गांवों में अवैध शराब का नेटवर्क सक्रिय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि नईगढ़ी क्षेत्र और आसपास के कई गांवों में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री और पैकारी का धंधा चल रहा है आरोप है कि गांवों में शराब निर्धारित कीमत से अधिक दामों पर बेची जाती है जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गई हैं लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से अवैध कारोबार पर अंकुश नहीं लग सका है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं प्रशासन की ओर से समय-समय पर नशा मुक्ति अभियान और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दावे किए जाते हैं लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है लोगों का तर्क है कि यदि नियमित अभियान चल रहे हैं तो फिर गांवों तक कथित शराब सप्लाई कैसे जारी है।

इस पूरे मामले ने जिले में निगरानी व्यवस्था और विभागीय समन्वय पर भी बहस छेड़ दी है स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को दर्शाएगा मामले में आबकारी इंस्पेक्टर अभिषेक त्रिपाठी से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका वहीं स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि इसमें कोई भी व्यक्ति या नेटवर्क संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई आवश्यक है ताकि न केवल अवैध शराब कारोबार पर रोक लगे, बल्कि जनता का प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत बना रहे।

सीएम राइज स्कूल निर्माण में सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोप, बिना हेलमेट काम करते मिले मजदूर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के आदिवासी अंचल कुसमी में करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे तीन मंजिला सीएम राइज स्कूल भवन का निर्माण कार्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विवादों में आ गया है निर्माण स्थल पर मजदूरों से बिना हेलमेट, सेफ्टी शूज़ और अन्य सुरक्षा उपकरणों के काम कराए जाने के आरोप सामने आए हैं। इसके साथ ही परियोजना के लिए 13 सरकारी भवनों को ध्वस्त किए जाने पर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं मामले में मजदूरों, निर्माण एजेंसी और अधिकारियों के अलग-अलग दावे सामने आए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस स्थान पर सीएम राइज स्कूल का निर्माण हो रहा है, वहां पहले आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन सहित कुल 13 सरकारी इमारतें मौजूद थीं ग्रामीणों का कहना है कि इनमें से 10 से अधिक भवन अच्छी स्थिति में थे और उनका उपयोग किया जा सकता था लेकिन सभी भवनों को तोड़ दिया गया इसे लेकर क्षेत्र में नाराजगी देखी जा रही है और लोग इस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। शुक्रवार शाम करीब चार बजे निर्माण स्थल के निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कार्य करते मिले तीन मंजिला भवन के निर्माण में कई श्रमिक ऊंचाई पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास न हेलमेट था और न ही सेफ्टी बेल्ट या सुरक्षा जूते इससे निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्माण कार्य में लगे बिहार निवासी मजदूर दीपक कुमार ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की ओर से उन्हें कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जाता उनका कहना है कि जब उन्होंने सुरक्षा सामग्री की मांग की तो उनसे कहा गया कि यदि काम करना है तो करें अन्यथा वापस चले जाएं और जरूरत हो तो सुरक्षा उपकरण स्वयं खरीद लें एक अन्य मजदूर रघुवीर ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाते हुए कहा कि जोखिम भरे माहौल में काम कराया जा रहा है लेकिन सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि निर्माण स्थल के सुपरवाइजर मनीष सिंह ने इन आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि सभी मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं लेकिन कई श्रमिक उनका उपयोग नहीं करते। उन्होंने कहा कि यदि मजदूर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे तो किसी दुर्घटना की जिम्मेदारी उनकी होगी दूसरी ओर, निरीक्षण के दौरान अधिकांश मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के ही काम करते दिखाई दिए। निर्माण एजेंसी पीएयू के कार्यपालन यंत्री कौशल परते ने कहा कि सभी ठेकेदारों को श्रमिकों को हेलमेट, सेफ्टी शूज़, बेल्ट और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं ।

रीवा के जलप्रपात बने डेथ प्वाइंट, सुरक्षा इंतजाम नदारद, रेलिंग और बैरिकेडिंग के बिना बढ़ा हादसों का खतरा

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मानसून की सक्रियता बढ़ते ही रीवा जिले के बहुती, चचाई, पूर्वा और इटमा जलप्रपातों पर पर्यटकों की भीड़ तेजी से बढ़ गई है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध ये स्थल बारिश के मौसम में आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। जिले के अधिकांश प्रमुख जलप्रपातों पर सुरक्षा इंतजाम नाकाफी बताए जा रहे हैं पूर्वा जलप्रपात को छोड़कर अन्य स्थानों पर कई जगहों पर सुरक्षा रेलिंग तक नहीं लगी है वहीं कई क्षेत्रों में गहरी खाई, तेज बहाव और फिसलन भरी चट्टानों के बावजूद पर्याप्त बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं इससे पर्यटकों की सुरक्षा लगातार खतरे में बनी हुई है। इटमा वाटरफॉल में हाल ही में डूबने की दो अलग-अलग घटनाओं में 21 वर्षीय सोनू खान (बरगढ़, उत्तर प्रदेश) और 23 वर्षीय सूर्यकांत कुमार (प्रयागराज) की मौत हो चुकी है लगातार हो रही इन घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास प्रवेश शुरू, 15 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जिले में संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है विभाग ने इच्छुक एवं पात्र छात्र-छात्राओं से 15 अगस्त 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित छात्रावास अधीक्षक अथवा अधीक्षिका के पास जमा किए जा सकेंगे विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि जिले में संचालित 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास, नौढ़िया (सीधी) तथा 50 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, सीधी में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इन छात्रावासों में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जो शासकीय अथवा अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत हों और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। विभाग के अनुसार आवेदन-पत्र संबंधित छात्रावासों से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं आवेदन के साथ संबंधित महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदन-पत्र पर संबंधित शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य का प्रमाणन भी आवश्यक रहेगा विभाग ने बताया कि छात्रावास में प्रवेश केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगा। प्रथम बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को एक हजार रुपये की काशन मनी (अवधान राशि) जमा करनी होगी यह राशि छात्रावास छोड़ने के समय निर्धारित नियमों के अनुसार वापस कर दी जाएगी प्रवेश प्रक्रिया छात्रावास प्रवेश नियमावली-2012 के प्रावधानों के अनुरूप पूरी की जाएगी। आवेदन के साथ आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, महाविद्यालय का एलॉटमेंट लेटर, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं का घोषणा-पत्र तथा माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति भी आवेदन के साथ देना आवश्यक है। सहायक संचालक ने बताया कि छात्रावास में प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना होगा यदि कोई छात्र-छात्रा आवेदन में गलत जानकारी देता है या छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। विभाग ने इच्छुक विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने की अपील की है, ताकि पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रावास की सुविधा का लाभ मिल सके। प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता और अन्य नियमों संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए विद्यार्थी संबंधित पोस्ट मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास, सीधी के अधीक्षक अथवा अधीक्षिका से संपर्क कर सकते हैं।

रीवा में जिला पंचायत सीईओ पर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का हमला

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने रीवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) मेहताब सिंह गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कार्यशैली की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए सीईओ की तुलना हर प्लेट पर मुंह मारने वाले टॉमी से की और उन्हें टपोरी तथा छोटी सोच वाला अधिकारी बताया विधायक ने कहा कि वह पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से करेंगे।

मीडिया से चर्चा के दौरान अभय मिश्रा ने कहा कि रीवा में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, आईजी गौरव राजपूत सहित अधिकांश अधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिला पंचायत सीईओ की कार्यशैली से प्रशासन की छवि प्रभावित हो रही है उन्होंने आरोप लगाया कि सीईओ केवल कमाई और लूटपाट के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं तथा जिले में विकास कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं विधायक ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत सीईओ ने अपने एजेंट नियुक्त कर रखे हैं और उन्हीं के माध्यम से विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं उनका दावा है कि विकास कार्यों में कमीशनखोरी हावी है जिससे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि यदि इस पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा अभय मिश्रा ने यह भी कहा कि कुछ समय पहले कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की कार्रवाई के विरोध में जिला पंचायत कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के पीछे भी जिला पंचायत सीईओ की भूमिका थी उस समय भी उन्होंने कलेक्टर को ईमानदार अधिकारी बताते हुए पूरे घटनाक्रम को सीईओ का षड़यंत्र करार दिया था। वहीं इस मामले में जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर का पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल विधायक के आरोपों पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सीधी में तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह संपन्न, नवप्रवेशित विद्यार्थियों को मिली नई शिक्षा नीति व व्यक्तित्व विकास की जानकारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, उपलब्ध सुविधाओं तथा व्यक्तित्व विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करना था कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रभाकर सिंह के निर्देशन में किया गया। समारोह के प्रथम दिवस नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का तिलक, माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया इसके बाद प्राचार्य डॉ. प्रभाकर सिंह ने महाविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, विभिन्न विभागों, संसाधनों एवं छात्रहित में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी डॉ. रविन्द्र नाथ सिंह ने खेल गतिविधियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जबकि डॉ. दिवाकर सिंह ने पुस्तकालय एवं इको क्लब की गतिविधियों से परिचित कराया। दूसरे दिन डॉ. अरविंद कुमार त्रिपाठी ने प्रवेश प्रक्रिया, विषय चयन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी वहीं डॉ. आई.पी. प्रजापति ने परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं स्वशासी व्यवस्था की जानकारी साझा की डॉ. विनोद प्रजापति ने विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से अवगत कराया इस दौरान डॉ. अरुणा सिंह ने लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र पर विस्तार से जानकारी देते हुए सुरक्षित एवं सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया।

स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति का विशाल सम्मेलन 5 जुलाई को रीवा में, तैयारियां अंतिम चरण में

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा 5 जुलाई 2026 को रीवा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इस सम्मेलन में देश एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि तथा संगठन के वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। जानकारी के अनुसार सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों का रीवा आगमन आज से प्रारंभ हो जाएगा इसी क्रम में 4 जुलाई को समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह रघुवंशी, राष्ट्रीय संगठन सचिव कपूर सिंह दलाल तथा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष

परमजीत सिंह टिवाना प्रातः 5 बजे रीवा पहुंचेंगे। इन राष्ट्रीय पदाधिकारियों के स्वागत के लिए समिति की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य, मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. राजा भैया मिश्रा, जिला अध्यक्ष रीवा डॉ. प्रसन्न सिंह परिहार सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहेंगे संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के अधिकारों, सम्मान तथा संगठन को मजबूत बनाना है।

सिंगरौली में 12 लाख की सड़क 15 दिन में उखड़ी, गुणवत्ता पर सवाल; महापौर ने किया निरीक्षण, दो अधिकारियों को नोटिस

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-24 नवानगर में हाल ही में बनी सड़क महज 15 दिन के भीतर ही उखड़ने लगी, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं करीब 12 लाख रुपये की लागत से बनी इस सड़क की खराब स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उन्होंने निर्माण में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया आरोप है कि डामर की मात्रा कम रखी गई और गिट्टी का असमान उपयोग किया गया जिससे सड़क की ऊपरी परत सामान्य आवाजाही और हल्की सफाई में ही उखड़ने लगी। बारिश से पहले ही सड़क की हालत बिगड़ने पर लोगों ने मौके पर ही विरोध जताते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम की महापौर रानी अग्रवाल मौके पर पहुंचीं और सड़क का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की स्थिति देखी और गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की महापौर ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए।

नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है साथ ही पूरे निर्माण कार्य की जांच के आदेश दिए गए हैं अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में लापरवाही या निर्धारित मानकों के विपरीत निर्माण पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। इस घटना के बाद नगर निगम के निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क का टिकाऊ न होना भ्रष्टाचार या लापरवाही की ओर इशारा करता है उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों नगर निगम प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी वहीं, स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि इस बार केवल जांच तक मामला सीमित नहीं रहेगा बल्कि वास्तविक कार्रवाई भी होगी ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह संपन्न, नवप्रवेशी छात्राओं का हुआ आत्मीय स्वागत

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीधी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की नवप्रवेशी छात्राओं के स्वागत एवं उन्हें महाविद्यालयीन वातावरण से परिचित कराने के उद्देश्य से तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का आयोजन उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को नई शिक्षा नीति-2020, महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, विभिन्न सुविधाओं तथा छात्र हितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई समारोह के प्रथम दिवस का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ इसके बाद महाविद्यालय परिवार ने भारतीय परंपरा के अनुसार नवप्रवेशी छात्राओं का तिलक लगाकर, पुष्प भेंट कर और शुभकामनाओं के साथ आत्मीय

स्वागत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. ओ.पी. नामदेव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने का केंद्र नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है उन्होंने छात्राओं से नियमित अध्ययन, अनुशासन तथा महाविद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, पुस्तकालय, आईसीटी सुविधाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना तथा रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। साथ ही शासन द्वारा संचालित विभिन्न छात्र हितैषी योजनाओं से भी अवगत कराया गया, ताकि छात्राएं महाविद्यालयीन जीवन में सहजता से स्वयं को ढाल सकें दूसरे दिन आयोजित सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख प्रावधानों पर विशेष चर्चा की गई ।

ये पाकिस्तान के पैरोकार

संपादकीय

भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों करे? राजनयिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पेशेवर रिश्ते क्यों बहाल करे? एक आतंकिस्तान देश को सबक सिखाना चाहिए अथवा संवाद के जरिए मुहब्बत का इजहार करना चाहिए? जो 117 चेहरे आज पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं, क्या वे भूल गए कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी जारी है? क्या वे पहलगाम का नरसंहार भूल गए? क्या पुलवामा में 40 'शहीदों' की कुर्बानी भूल गए? क्या उरी से लेकर 26/11 मुंबई आतंकी हमले तक पाकपरस्त शैतानों और हत्यारों की साजिशें भी भूल गए? क्या इन पैरोकारों ने आतंकवाद में अपने किसी परिजन को खोया है? यह पीड़ा, हत्या, दर्द, खालीपन, सूने आंगन, उजड़े सिंदूर को कैसे और कौन भूल सकता है? आखिर भारत की मजबूरी क्या है, जो वह पाकिस्तान की आतंकी, हत्यारी हुकूमत के साथ बातचीत करे? इस भूखे, नंगे, कर्जदार देश के पल्ले क्या है, जो वह भारत को मुहैया करा सकता है? और फिर क्या गारंटी है कि संवाद और संबंधों की बहाली के बाद सरहदों पर तनाव ठहर जाएगा? सीमापार से आतंकी भेजे नहीं जाएंगे? वैश्विक मंचों पर, कश्मीर की आड़ में, भारत-विरोधी दुष्प्रचार थम जाएंगे? सांप की फितरत बदली है कभी? जिन 117 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और कथित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुला पत्र लिख कर भारत-पाक संवाद और बेहतर, कारगर संबंधों की गुहार की है, उनमें जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर और सैफुद्दीन सोज भी शामिल हैं। मणिशंकर ने सलमान खुर्शीद के साथ पाकिस्तान जाकर गुहार की थी कि मोदी सरकार हटाने में मदद करें। यह नवंबर, 2015 का वाकया है। दोनों कथित कांग्रेस नेताओं का कहना था कि मोदी को हटाए बिना भारत-पाक संबंध बेहतर नहीं हो सकते। अब पैरोकारों की सूची में शामिल हैं, तो वह बिल्कुल बेमानी है।

खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रहे एएस दुल्लत भी सूची में हैं, जो पाकिस्तान की रूह तक से वाकिफ हैं और कई आतंकी हमलों के साक्षी रहे हैं। ओपी शाह, मनोज झा, जवाहर सरकार आदि कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, यह हम नहीं जानते, लेकिन सूची में जो 61 नाम भारतीयों के हैं, वे यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर विरोधी हैं और पाकपरस्त चेहरे हैं। आज उन्हें कौन पूछता है? क्या प्रासंगिकता है इनकी? क्या इनमें से किसी ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि आतंकी सांपों को पालना बंद करें? उनके अड्डे खत्म किए जाएं। हुकूमत और फौज आतंकियों की आर्थिक मदद करना और उन्हें 'जेहादी समर्थन' देना भी बंद करें।

बाल पुरस्कारों के लिए मप्र के बच्चों का आह्वान

डॉ. निवेदिता शर्मा

भारत प्रतिभाओं की धरती है। यहां के गांवों, कस्बों और शहरों में ऐसे हजारों बच्चे हैं, जो अपनी उम्र से कहीं आगे बढ़कर समाज, पर्यावरण, विज्ञान, खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। कोई कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई जारी रखते हुए वैज्ञानिक सोच के साथ नवाचार कर रहा है, कोई जल और जंगल बचाने का अभियान चला रहा है, कोई राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में नाम रोशन कर रहा है, तो कोई अपनी संवेदनशीलता और साहस से समाज के लिए मिसाल बन रहा है। स?वभाविक है इस कार्य को मध?य प्रदेश के हमारे अपने अनेकों बच?चे भी कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य यह है कि इनमें से अनेक बच्चों की प्रेरक कहानियां स्थानीय स्तर तक ही सीमित रह जाती हैं।

वास?तव में ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों से 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' के लिए अधिक से अधिक नामांकन भेजने का आह्वान किया गया है। यह पुरस्कार उस सोच का सम्मान है, जो यह सिद्ध करती है कि परिवर्तन लाने के लिए बड़ी उम्र नहीं, बड़ा संकल्प चाहिए। यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो तो छोटी उम्र में भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जोकि पांच से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने असाधारण धैर्य, साहस, सृजनात्मकता और अदम्य जज़्बे का परिचय दिया हो। प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति इन प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करते हैं। पुरस्कार छह श्रेणियों, जिसमें कि बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शामिल हैं, मेंप्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर किया जाता है।

यह दिवस दसवें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों, साहिबज़ादा जोरावर सिंह और साहिबज़ादा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान और नैतिक साहस की स्मृतियों को याद करने के लिए है। मात्र नौ और सात वर्ष की आयु में अपने सिद्धांतों और आस्था से समझौता न करने वाले इन वीर बालकों का जीवन आज भी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उसी अमर परंपरा को वर्तमान पीढ़ी की उपलब्धियों से जोड़ने का माध्यम है, जहां साहस, सेवा, समर्पण और उत्कृष्टता को राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है।

वर्ष 2019 में इस पुरस्कार की नई व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक देशभर के 203 बच्चों को सम्मानित किया जा चुका है। इन बच्चों की उपलब्धियां विविध क्षेत्रों में रही हैं। किसी ने बाढ़ या आग जैसी आपदा में लोगों की जान बचाई, किसी ने वैज्ञानिक उपकरण विकसित किए, किसी ने दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी तकनीक बनाई, किसी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हजारों लोगों को जागरूक किया, तो किसी ने खेल या कला के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाया। इन प्रेरक कहानियों ने यह साबित किया है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर, संसाधन या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती।

मध्य प्रदेश में भी ऐसी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जनजाति अंचलों से लेकर नगर, महानगरों तक अनेक बच्चे अपनी मेहनत और रचनात्मकता से नई पहचान बना रहे हैं। अलग-अलग दिशा में हमारे बच?चे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब ऐसे बच्चों के कार्यों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए आवश्यक है कि समय रहते उनका नामांकन किया जाए।

अब जिन छह श्रेणियों में यह पुरस?कार दिया जाता है, उनमें अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता की हो या संकट की घड़ी में अद्वितीय साहस और सूझबूझ का परिचय दिया हो, उसे बहादुरी के अंतर्गत सम?मान ये सम?मान मिलता है। समाज सेवा श्रेणी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों या समुदाय के हित में प्रेरणादायी कार्य किए हों।

मोदी का मिशन 360: सत्ता के सुपर बहुमत की राजनीति या लोकतंत्र का नया अध्याय?

विनोद कुमार सिंह तकियावाला

भारतीय राजनीति में इन दिनों एक शब्द तेजी से चर्चा के केंद्र में है - मोदी महामिशन मिशन 360।यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने इस नाम से किसी आधिकारिक अभियान की घोषणा नहीं की है, फिर भी सत्ता और विपक्ष के राजनीतिक गलियारों में यह धारणा तेजी से मजबूत हो रही है कि भाजपा आगामी वर्षों में संसद के दोनों सदनों में ऐसा संख्याबल अर्जित करने की रणनीति पर काम कर रही है,जिससे न केवल राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हो, बल्कि संवैधानिक एवं नीतिगत सुधारों को भी अपेक्षाकृत सहजता से आगे बढ़ाया जा सके।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल अगले चुनाव की तैयारी नहीं,बल्कि दीर्घकालिक राजनीतिक वर्चस्व की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।वही दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संतुलन के लिए चुनौती बताते हुए आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्षी दलों में राजनीतिक सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है।सत्य चाहे जो हो,इतना स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति एक नए संक्रमणकाल से गुजर रही है, जहाँ चुनावी जीत के साथ-साथ संसदीय गणित, गठबंधन प्रबंधन और संवैधानिक व्याख्याएँ भी सत्ता की दिशा तय कर रही हैं।भारतीय संविधान किसी भी राजनीतिक दल को व्यापक जनादेश प्राप्त करने से नहीं रोकता।लोकतंत्र का मूल आधार ही जनता का विश्वास है।यदि कोई दल चुनाव जीतकर या वैधानिक गठबंधन के माध्यम से बहुमत प्राप्त करता है तो उसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है।किंतु जब बहुमत प्राप्त करने की प्रक्रिया विपक्षी दलों में टूट,निर्वाचित प्रतिनिधियों के दल परिवर्तन अथवा राजनीतिक पुनर्संरेखण के माध्यम से आगे बढ़ती दिखाई देती है,तब लोकतांत्रिक नैतिकता पर बहस स्वाभाविक हो जाती है।यही कारण है कि आज मोदी महामिशन 360 केवल एक राजनीतिक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की दिशा को लेकर उठ रहे अनेक प्रश्नों का प्रतीक बन चुका है।लोकसभा में साधारण बहुमत सरकार चलाने के लिए पर्याप्त होता है,किंतु संविधान संशोधन जैसे विषयों पर विशेष बहुमत आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अनेक संशोधनों के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए तथा कुछ मामलों में आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है।इसलिए किसी भी सरकार के लिए केवल सत्ता में बने रहना पर्याप्त नहीं, बल्कि संसद में व्यापक संख्याबल भी राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।इसी संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महिला आरक्षण कानून के पूर्ण क्रियान्वयन, परिसीमन,एक देश- एक चुनाव,प्रशासनिक सुधार तथा भविष्य के अन्य संवैधानिक विषयों को देखते हुए भाजपा अपनी संसदीय शक्ति को और विस्तृत करना चाहती है।ज्ञायत्व रहे कि भारतीय राजनीति में दल-बदल कोई नया अध्याय नहीं है।वर्ष 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल के बार-बार दल बदलने के बाद आया राम,गया राम भारतीय राजनीति का स्थायी मुहावरा बन गया।इसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए 1985 में संविधान की दसवीं अनुसूची के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया।बाद में 91वें संविधान संशोधन (2003) ने इसे और कठोर बनाया।

फिर भी पिछले एक दशक की राजनीति ने यह दिखाया कि कानून होने के बावजूद राजनीतिक पुनर्सरचना पूरी तरह नहीं रुकी।सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र रहा। पहले शिवसेना में विभाजन हुआ और बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी दो हिस्सों में बंट गई।इन घटनाओं ने केवल सरकार नहीं बदली,बल्कि दल-बदल कानून की व्याख्या, विधानसभा अध्यक्ष की संवैधानिक भूमिका,निर्वाचन आयोग की शक्तियों तथा सर्वोच्च न्यायालय की सीमाओं पर भी व्यापक बहस छेड़ दी।सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्वाचित जनादेश और संवैधानिक मर्यादा दोनों की रक्षा आवश्यक है, किंतु अनेक परिस्थितियों में अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र से भी जुड़ा रहता है। इससे यह संदेश गया कि आज राजनीतिक लड़ाई केवल विधानसभा या संसद में नहीं,बल्कि न्यायालयों में भी लड़ी जा रही है।मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तन,कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन तथा विभिन्न राज्यों में दल-बदल की घटनाओं ने यह स्थापित किया कि संख्या का खेल अब केवल चुनाव परिणामों से तय नहीं होता, बल्कि चुनाव के बाद की राजनीतिक रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है।पश्चिम बंगाल भी इस बहस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में कई नेताओं के दल बदलने की घटनाएँ सामने आई।कुछ नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, जबकि बाद में कुछ पुनः वापस लौटे।इन घटनाओं ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या भारतीय राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता कमजोर हो रही है और चुनावी गणित अधिक प्रभावी बनता जा रहा है।दिल्ली और पंजाब की राजनीति में भी समय-समय पर आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों और नेताओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक अटकलें सामने आती रही हैं।हालाँकि अधिकाँश मामलों में न तो इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि हुई और न ही वे निर्णायक राजनीतिक घटनाक्रम में बदलीं,लेकिन इससे यह संकेत अवश्य मिलता है कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक सांसद और प्रत्येक क्षेत्रीय दल भविष्य के सत्ता समीकरण का संभावित हिस्सा माना जा रहा है।यहीं से मोदी महामिशन 360 की चर्चा को बल मिलता है।यदि किसी राजनीतिक दल का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं,बल्कि संसद में इतना व्यापक समर्थन प्राप्त करना हो कि भविष्य के बड़े संवैधानिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा सके,तो स्वाभाविक रूप से उसकी रणनीति केवल चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं रह सकती।यद्यपि भाजपा इस प्रकार की राजनीतिक चर्चाओं पर सार्वजनिक रूप से संयमित रुख अपनाती रही है,लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई,राजनीतिक दबाव और सत्ता के प्रभाव का उपयोग विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है।दूसरी ओर भाजपा का तर्क रहा है कि यदि विपक्ष के नेता स्वयं उसके साथ जुड़ते हैं तो वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है और जनता अंततः चुनाव में इसका निर्णय करती है।यहीं भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है -क्या दल बदलना जनादेश का सम्मान है या जनादेश का पुनर्लेखन?संविधान विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि भारतीय संविधान किसी सांसद या विधायक को आजीवन किसी दल से बंधा रहने का आदेश नहीं देता,किंतु दसवीं अनुसूची का उद्देश्य व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचित जनादेश को बदलने से रोकना अवश्य है।इसलिए यदि कानून की भावना और राजनीतिक व्यवहार के बीच लगातार दूरी बढ़ती है,तो भविष्य में दल-बदल विरोधी कानून की पुर्नसमीक्षा की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता।भारतीय राजनीति का मौजूदा दौर केवल सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का नहीं, बल्कि राजनीतिक संगठन क्षमता,नेतृत्व,वैचारिक विस्तार और संसदीय अंकगणित की प्रतिस्पर्धा का भी है।

'गणेश सिंह क्या हैं?'

बेदान्ती त्रिपाठी

लगातार पांच बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसद गणेश सिंह की राजनीतिक सफलता को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर उनकी लोकप्रियता का आधार क्या है। विभिन्न चुनावों में कई मजबूत प्रतिद्वंद्वी उनके सामने उतरे, लेकिन वे लगातार जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। उनके समर्थकों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह चुनावी राजनीति से अधिक जनता के बीच उनकी निरंतर सक्रिय मौजूदगी और सेवा का भाव है। राजनीतिक विश्लेषकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकांश जनप्रतिनिधि चुनाव के समय ही जनता के बीच सक्रिय दिखाई देते हैं जबकि गणेश सिंह वर्षभर अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के संपर्क में रहते हैं गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनना, अधिकारियों से समन्वय कर उनका समाधान कराने का प्रयास करना और अपने कार्यालय में प्रतिदिन आने वाले लोगों से सीधे संवाद करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा माना जाता है। यही कारण है कि चुनाव के समय उन्हें अलग से अपना परिचय देने या बड़े चुनावी वादे करने की आवश्यकता कम पड़ती है उनके समर्थकों का यह भी कहना है कि गणेश सिंह का सरल, सहज और मिलनसार स्वभाव उन्हें आम लोगों के करीब रखता चाहे किसी व्यक्ति का छोटा काम हो या बड़ा, वे उसे गंभीरता से सुनने और समाधान का प्रयास करने के लिए जाने जाते है समर्थकों के अनुसार यही अपनापन उनके प्रति मतदाताओं का भरोसा लगातार मजबूत करता रहा है गणेश सिंह के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि उनके लंबे राजनीतिक जीवन में उनके विरोधी भी उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप स्थापित नहीं कर पाए हालांकि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा रहे हैं लेकिन उनके समर्थक इसे उनकी साफ-सुथरी छवि का प्रमाण मानते हैं। हाल ही का एक उदाहरण भी उनके समर्थक उनकी कार्यशैली से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। सतना के मारुति नगर निवासी एक युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था जबलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। बाद में अन्य अस्पतालों में भी उसे तत्काल राहत नहीं मिल सकी। परिजनों ने अंततः सांसद गणेश सिंह से सहायता मांगी। इसके बाद उनके प्रयासों से युवक को भोपाल स्थित एम्स में भर्ती कराया गया जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उपचार किया। चिकित्सकीय स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों को युवक का पैर काटना पड़ा, लेकिन परिजनों के अनुसार उपचार की व्यवस्था कराने और लगातार हालचाल लेने में सांसद की सक्रिय भूमिका रही। समर्थकों का मानना है कि यही मानवीय दृष्टिकोण, व्यक्तिगत संपर्क और लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया गणेश सिंह को अन्य नेताओं से अलग पहचान देता है। उनके अनुसार राजनीति केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का सतत दायित्व है।

थकी हुई वर्दी, टूटता हुआ मन

किसी भी देश की कानून-व्यवस्था का सबसे दृश्यमान चेहरा पुलिस होती है। जब कोई अपराध होता है, दुर्घटना घटती है, दंगा भड़कता है, प्राकृतिक आपदा आती है या किसी नागरिक को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले पुलिस ही सामने दिखाई देती है। समाज उससे हर समय तत्पर, अनुशासित, निष्पक्ष और संवेदनशील रहने की अपेक्षा करता है। विडंबना यह है कि जो व्यवस्था पूरे समाज को सुरक्षा का भरोसा देती है, उसी व्यवस्था के भीतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों की मानसिक सुरक्षा और भावनात्मक आवश्यकताओं पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

बाहर से रोबदार दिखने वाली वर्दी के भीतर भी एक संवेदनशील मन धड़कता है, जो लगातार बढ़ते तनाव, कार्यभार, पारिवारिक दूरियों और संस्थागत दबावों के बीच धीरे-धीरे टूटता चला जाता है।

हाल ही में पुलिस इंस्पेक्टर श्रवण कुमार बिश्नोई की आत्महत्या की खबर ने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया। किसी भी आत्महत्या के पीछे के कारणों का अंतिम निर्धारण केवल आधिकारिक जांच से ही संभव है इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं होगा। फिर भी यह दुखद घटना पुलिस बल में मानसिक तनाव, कार्य संस्कृति और मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यह केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं बल्कि उस व्यवस्था का आईना भी है, जहाँ कर्तव्य निभाते-निभाते कई बार इंसान स्वयं अपने भीतर हारने लगता है।

हमारे समाज में पुलिस की छवि अक्सर अधिकार, शक्ति और कठोरता से जुड़ी रही है। आम नागरिक मान लेते हैं कि पुलिसकर्मी भावनाओं से परे होते हैं, उन्हें दर्द नहीं होता, वे कभी नहीं टूटते। यही सबसे बड़ी भूल है। पुलिसकर्मी भी उसी समाज के सदस्य हैं। वे भी किसी के बेटे-बेटी, पति-पत्नी, माता-पिता और मित्र होते हैं। उन्हें भी अपनों की चिंता होती है, आर्थिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं और भावनात्मक सहारे की आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना है कि वे अपने दुख को अक्सर वर्दी के भीतर छिपाकर रखना सीख जाते हैं। पुलिस सेवा का वास्तविक स्वरूप फिल्मों और धारावाहिकों से बिल्कुल अलग है। अधिकांश पुलिसकर्मियों का दिन कब शुरू होता है और कब समाप्त, इसका निश्चित समय नहीं होता। आठ घंटे की ड्यूटी का सिद्धांत व्यवहार में शायद ही कहीं पूरी तरह लागू दिखाई देता है। त्योहार हो, चुनाव हो, वीआईपी दौरे हों, धरना-प्रदर्शन हो, प्राकृतिक आपदाएँ हों या अपराध की गंभीर घटनाएँ- हर स्थिति में सबसे पहले पुलिस को तैनात किया जाता है। कई बार लगातार चौबीस-चौबीस घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। पर्याप्त नींद, नियमित भोजन और पारिवारिक समय उनके जीवन में विलासिता बन जाते हैं।

विश्व भर के मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लगातार नींद की कमी, अत्यधिक कार्यभार और भावनात्मक तनाव किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। पुलिसकर्मी प्रतिदिन हत्या, आत्महत्या, सड़क दुर्घटना, घरेलू हिंसा, यौन अपराध और अन्य दर्दनाक घटनाओं का सामना करते हैं। सामान्य नागरिक जिन दृश्यों को केवल समाचारों में देखते हैं, पुलिस उन्हें प्रत्यक्ष रूप से झेलती है। ऐसे अनुभव धीरे-धीरे मन पर गहरे घाव छोड़ते हैं। यदि समय पर भावनात्मक सहयोग न मिले तो यही दबाव अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ेपन और कई बार आत्मघाती विचारों तक पहुँच सकता है।

पुलिस व्यवस्था की आंतरिक संरचना भी कई बार तनाव को बढ़ा देती है। वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव, समयबद्ध परिणाम देने की अपेक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप, संसाधनों की कमी और निरंतर जवाबदेही अधीनस्थ कर्मचारियों के मानसिक बोझ को कई गुना बढ़ा देती है। अनुशासन किसी भी सुरक्षा बल की आवश्यकता है लेकिन अनुशासन और मानवीय संवेदनशीलता का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। यदि अधीनस्थ कर्मचारी अपनी समस्याएँ खुलकर साझा करने से डरने लगें तो तनाव भीतर ही भीतर विस्फोटक रूप ले सकता है

पारिवारिक जीवन भी पुलिस सेवा की सबसे बड़ी कीमत चुकाता है। पुलिसकर्मी अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते, माता-पिता की बीमारी में उपस्थित नहीं हो पाते और कई बार पारिवारिक समारोहों तक में शामिल नहीं हो पाते। लगातार अनुपस्थिति से परिवारों में भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है। कई पुलिसकर्मी अपने व्यक्तिगत तनाव को परिवार से छिपाते हैं ताकि घर वाले चिंतित न हों, जबकि परिवार अपनी समस्याएँ उनसे इसलिए नहीं कह पाता कि वे पहले ही बहुत तनाव में हैं। यह मौन धीरे-धीरे मानसिक अकेलेपन में बदल जाता है।

समाज भी इस समस्या को पूरी गंभीरता से नहीं समझता। जब पुलिस कोई गलती करती है तो आलोचना स्वाभाविक है। जवाबदेही लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है। लेकिन हर पुलिसकर्मी को केवल कठोर, असंवेदनशील या भ्रष्ट मान लेना न्यायसंगत नहीं है। हजारों पुलिसकर्मी सीमित संसाधनों और अत्यधिक दबाव के बीच ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। वे भी सम्मान और संवेदनशील व्यवहार के अधिकारी हैं।

चिंताजनक बात यह है कि पुलिस बल में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलापन आज भी पर्याप्त नहीं है। यदि कोई कर्मचारी मनोवैज्ञानिक सहायता लेना चाहता है तो कई बार उसे कमजोरी समझ लिया जाता है। परिणामस्वरूप अनेक लोग अपने भीतर की पीड़ा को वर्षों तक दबाए रखते हैं। वे मुस्कुराते हुए ड्यूटी करते हैं लेकिन भीतर से टूटते रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर चुप्पी किसी भी संस्था के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अब समय केवल संवेदना व्यक्त करने का नहीं बल्कि ठोस सुधारों का है। सबसे पहले पुलिसकर्मियों के कार्य घंटे यथासंभव मानवीय बनाए जाने चाहिए। पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति कर कार्यभार का न्यायसंगत वितरण किया जाए। लगातार ड्यूटी के बाद अनिवार्य विश्राम सुनिश्चित हो। साप्ताहिक अवकाश और पारिवारिक समय केवल कागजों तक सीमित न रहें। प्रत्येक जिले में पेशेवर मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। गोपनीय काउंसलिंग, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम, हेल्पलाइन और नियमित मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनाए जाने चाहिए। जैसे शारीरिक फिटनेस आवश्यक है, वैसे ही मानसिक फिटनेस भी पुलिस सेवा की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए।

पुलिस नेतृत्व को भी अपनी कार्यशैली में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। अच्छे नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं बल्कि अपने अधीनस्थों की परिस्थितियों को समझना भी है। यदि वरिष्ठ अधिकारी संवाद, सहयोग और विश्वास का वातावरण बनाएँ तो अनेक मानसिक संकट प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त हो सकते हैं। तकनीकी सुधार भी तनाव कम करने में सहायक हो सकते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, आधुनिक संचार प्रणाली, पर्याप्त वाहन, बेहतर उपकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण पुलिसकर्मियों के अनावश्यक बोझ को कम कर सकते हैं। जब कार्यकुशलता बढ़ेगी तो मानसिक दबाव भी घटेगा।

पुलिस परिवारों को भी सहायता तंत्र से जोड़ा जाना चाहिए। पारिवारिक परामर्श, सामुदायिक समर्थन समूह और नियमित संवाद कार्यक्रम पुलिसकर्मियों तथा उनके परिजनों को भावनात्मक सहारा प्रदान कर सकते हैं। एक मजबूत परिवार मानसिक तनाव के विरुद्ध सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच होता है। मीडिया और समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस की कमियों को उजागर करना लोकतांत्रिक आवश्यकता है।

कलेक्टर कार्यालय परिसर में एसबीआई के नए एटीएम का शुभारंभ, नागरिकों को मिलेगी 24×7 बैंकिंग सुविधा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नए एटीएम का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और फीता काटकर एटीएम का विधिवत लोकार्पण किया इस नई सुविधा से कलेक्टर कार्यालय आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को 24 घंटे बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सकेगा इस अवसर पर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कहा कि कलेक्टर कार्यालय परिसर में एटीएम स्थापित होने से लोगों को नकदी निकासी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा एक ही स्थान पर आवश्यक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने से समय की बचत होगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आमजन को आधुनिक और सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने कहा कि आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है डिजिटल और सहज बैंकिंग व्यवस्था से न केवल लोगों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि नकदी प्रबंधन भी अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगा उन्होंने विश्वास जताया कि यह एटीएम आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगा बैंक अधिकारियों ने बताया कि नए एटीएम के शुरू होने से कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं आसपास के नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को 24×7 नकदी निकासी, बैलेंस इन्क्वायरी, मिनी स्टेटमेंट सहित अन्य एटीएम आधारित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी इससे बैंक शाखा पर निर्भरता कम होगी और लोगों को किसी भी समय आवश्यक बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंबिकापुर के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रतीक अग्निहोत्री ने कहा कि बैंक का उद्देश्य ग्राहकों तक बेहतर और आधुनिक सेवाएं पहुंचाना है वहीं जिला अग्रणी प्रबंधक बिजन नायक तथा मनेन्द्रगढ़ शाखा प्रबंधक उदय सिंह लोधी ने बताया कि जिले में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें। इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी एवं कर्मचारी, कलेक्टर कार्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि यह नई सुविधा आम नागरिकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के साथ जिले में डिजिटल बैंकिंग को भी नई गति प्रदान करेगी।

खबर प्रकाशित होते ही हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंची मेडिकल टीम

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर पर त्वरित संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाकर संवेदनशीलता का परिचय दिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अविनाश खरे के निर्देश पर विकासखंड भरतपुर की ग्राम पंचायत धोवाताल के आश्रित ग्राम मनटोलिया (बरेल) में रहने वाले समयलाल पंडो और उनकी पत्नी रूक्मन पंडो के घर विशेष स्वास्थ्य टीम भेजी गई टीम ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मौके पर ही उपचार शुरू किया तथा आवश्यक दवाइयां निशुल्क उपलब्ध कराईं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार समाचार प्रकाशित होने के बाद सीएमएचओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिकारियों को बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंचने के निर्देश दिए स्वास्थ्य टीम ने घर पहुंचकर दोनों की विस्तृत चिकित्सकीय जांच की और उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार उपचार शुरू किया। साथ ही परिजनों को दवाइयों के नियमित सेवन, खानपान और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सावधानियों की जानकारी भी दी गई ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से बचा जा सके। सीएमएचओ डॉ. अविनाश खरे ने बताया कि समयलाल पंडो उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य टीम ने उनका रक्तचाप परीक्षण किया और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराईं उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पहले से ही उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच करते रहे हैं और आगे भी यह व्यवस्था जारी रहेगी जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि रूक्मन पंडो पूर्व में कुष्ठ रोग से पीड़ित थीं लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों और उपचार के कारण अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं वर्तमान में उन्हें बढ़ती उम्र से जुड़ी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक दवाइयां दी गई हैं सीएमएचओ ने संबंधित चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से बुजुर्ग दंपत्ति के घर का भ्रमण करें साथ ही उनकी स्वास्थ्य स्थिति की सतत निगरानी रखने और समय पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि उन्हें उपचार के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े स्वास्थ्य विभाग की इस त्वरित और मानवीय पहल की क्षेत्र के ग्रामीणों ने सराहना की है ग्रामीणों का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों तक समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही का सकारात्मक उदाहरण है इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि समाचारों और जनसमस्याओं पर प्रशासन तत्परता से कार्रवाई कर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मॉब लिंचिंग मामले में फैसला सुनाने वाली जज को धमकी, हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। चर्चित मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने वाली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) तबस्सुम खान को सोशल मीडिया पर कथित जान से मारने और हिंसा की धमकियां मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) से तीन दिन के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं अगली सुनवाई 9 जुलाई को निर्धारित की गई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी न्यायिक अधिकारी को केवल इसलिए धमकाया नहीं जा सकता क्योंकि उसका फैसला किसी वर्ग को पसंद नहीं आया। अदालत ने कहा कि इस प्रकार की धमकियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर दबाव बनाने का प्रयास हैं और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए मामला 12 जून को सुनाए गए उस फैसले से जुड़ा है जिसमें एडीजे तबस्सुम खान ने एक चर्चित मॉब लिंचिंग प्रकरण में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए, जिनमें कथित तौर पर फैसले का विरोध करते हुए न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे बयान दिए गए एक वीडियो में कथित तौर पर यह कहा गया कि यदि दोषियों को रिहा नहीं किया गया तो व्यापक हिंसा होगी जबकि दूसरे वीडियो में न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत और सांप्रदायिक टिप्पणी की गई। मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेते हुए दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है थाना प्रभारी सुधाकर बारस्कर ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक सांई कृष्णा एस. थोटा ने बताया कि सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने, धमकी देने या सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री साझा करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है अब तक करीब 150 सोशल मीडिया अकाउंट चिन्हित किए गए हैं, जिनसे आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट की गई थी। इनमें से कई पोस्ट और लिंक हटवाए जा चुके हैं, जबकि संबंधित अकाउंट धारकों की जानकारी फेसबुक और इंस्टाग्राम से मांगी गई है उनकी पहचान होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उधर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (स्क्रह्न) ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि किसी भी न्यायिक आदेश से असहमति होने पर उसका समाधान अपीलीय अदालत में चुनौती देकर किया जाना चाहिए न्यायाधीशों को धमकाना या उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है पुलिस ने एडीजे की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच जारी है।

6 वर्षीय मासूम का अंगूठा काटने का आरोप, पिता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम के साथ कथित रूप से हुई बर्बरता का मामला सामने आया है बच्चे के पिता ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) से शिकायत कर आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के दो लोगों ने उनके छह वर्षीय बेटे के बाएं हाथ का अंगूठा और एक उंगली कुल्हाड़ी से काट दी शिकायत में आरोपियों पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और झूठा मामला दर्ज कराने का भी आरोप लगाया गया है वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी बदरवास थाना क्षेत्र के ग्राम मदनपुर निवासी रामवीर गुर्जर के अनुसार, बुधवार शाम करीब चार बजे उनका बेटा सचिन घर के बाहर खेल रहा था आरोप है कि गांव के आनंद गुर्जर और उदयभान गुर्जर उसे अपने घर ले गए, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से उसके बाएं हाथ का अंगूठा और एक उंगली काट दी गई जबकि तीसरी उंगली भी गंभीर रूप से घायल हो गई घायल बच्चा किसी तरह रोते हुए घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना बताई शिकायत में भूपेंद्र गुर्जर और रामहेत गुर्जर को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला स्तरीय कार्यशाला, अक्टूबर से पहले 22 ग्राम पंचायतों में होगा शत-प्रतिशत पालन

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अंकिता सोम की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में प्रथम चरण के लिए चयनित 22 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव तथा घर-घर कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण का कार्य करने वाली स्वच्छता दीदियों ने भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 1 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 लागू किए गए हैं इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाना, वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाना है उन्होंने अधिकारियों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि सभी चयनित पंचायतें पाक्षिक कार्ययोजना तैयार कर अक्टूबर 2026 से पहले नियमों के सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण सत्र में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियों और नियमों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई इसमें नियमित डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीले, सूखे, सैनिटरी और जोखिमपूर्ण कचरे का अलग-अलग संग्रहण, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देने, खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर प्रतिबंध, बल्क वेस्ट जनरेट करने वाले संस्थानों का चिन्हांकन एवं पंजीयन तथा नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया इसके तहत दीवार लेखन, चौपाल, ग्राम सभाएं, रैली और अन्य सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से लोगों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाएगा अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता अभियान तभी सफल होगा जब प्रत्येक ग्रामीण परिवार कचरे के पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता से जनपदवार कार्ययोजना तैयार कर जनसहभागिता आधारित चौपालों का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार परिवर्तन लाकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना और स्वच्छता को जनआंदोलन का रूप देना है।

अवैध रेत-गिट्टी परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर जब्त

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने खड़गवां और मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाते हुए अवैध रूप से रेत और गिट्टी का परिवहन कर रहे पांच ट्रैक्टर जब्त किए हैं जब्त वाहनों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 जुलाई 2026 को तहसील खड़गवां के ठगगांव क्षेत्र में जांच के दौरान उड़नदस्ता दल ने बिना वैध अनुमति गिट्टी का परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टर तथा रेत का अवैध परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ा जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर तीनों वाहनों को जब्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना खड़गवां में सुरक्षित खड़ा कराया गया। इसी प्रकार मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में भी विभागीय टीम ने अभियान के दौरान दो अन्य ट्रैक्टरों को अवैध रूप से रेत और गिट्टी का परिवहन करते हुए पकड़ा इन दोनों वाहनों को जब्त कर कलेक्टोरेट परिसर में सुरक्षित रखा गया है सभी मामलों में दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जा रहा है उड़नदस्ता दल संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रहा है ताकि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर रोक लगाई जा सके विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन संचालक को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनिज परिवहन से शासन को राजस्व की हानि होने के साथ-साथ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसी कारण जिले में इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी अधिकारियों ने वाहन मालिकों और खनिज परिवहन से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे केवल वैध अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही खनिजों का परिवहन करें तथा शासन के नियमों का पालन करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के विरुद्ध इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

8 बीघा जमीन विवाद में पिता-पुत्र पर हमला, लाठी-डंडों से पीटकर किया घायल

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के लाड़करन गांव में जमीन विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर कथित रूप से लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है जिला अस्पताल में भर्ती संजीव परिहार (32) ने बताया कि उनकी 8 बीघा कृषि भूमि पर खेरौना गांव के भरत रावत और हजारी रावत ने कब्जा कर रखा था करीब दो माह पहले राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन कराकर जमीन से कब्जा हटवाया गया था इसके बाद उन्होंने तीन दिन पहले अपने खेत की जुताई कराई थी। संजीव के अनुसार गुरुवार शाम सूचना मिली कि भरत रावत और हजारी रावत दोबारा ट्रैक्टर से उनकी जमीन जोत रहे हैं इस पर वह अपने पिता राम सिंह परिहार (52) के साथ खेत पहुंचे और विरोध किया आरोप है कि वहां पहले से मौजूद भरत रावत, हजारी रावत, राजेश रावत, बुद्धा, टिल्लू, बलवीर रावत सहित 10 से 12 लोगों ने लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से दोनों पर हमला कर दिया हमले में पिता-पुत्र घायल होकर खेत में गिर पड़े घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए परिजन दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उनका इलाज जारी है तेंदुआ थाना प्रभारी नीतू सिंह धाकड़ ने बताया कि घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

14-15 जुलाई को कांग्रेस की 'युवा स्वाभिमान Gen साइक्लोथॉन', भोपाल में होगा मुख्यमंत्री निवास का घेराव

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। प्रदेश कांग्रेस 14 और 15 जुलाई को युवाओं के मुद्दों को लेकर 'युवा स्वाभिमान GenZ साइक्लोथॉन' आयोजित करेगी यह साइकिल यात्रा इंदौर से शुरू होकर देवास, आष्टा और सीहोर होते हुए भोपाल पहुंचेगी कांग्रेस नेताओं के अनुसार यात्रा के समापन पर बड़ी संख्या में युवा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और रोजगार, शिक्षा सहित अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे इस संबंध में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शुक्रवार को उज्जैन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उज्जैन के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश का युवा आज बेरोजगारी, शिक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर चिंताओं से जूझ रहा है उनका आरोप था कि राज्य सरकार इन मुद्दों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य इस साइक्लोथॉन के माध्यम से युवाओं की आवाज को प्रदेश सरकार तक पहुंचाना और उनके अधिकारों के लिए जनआंदोलन खड़ा करना है वर्मा ने बताया कि 'युवा स्वाभिमान GenZ साइक्लोथॉन' की शुरुआत इंदौर से होगी यात्रा देवास, आष्टा और सीहोर से गुजरते हुए भोपाल पहुंचेगी, जहां हजारों युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे कांग्रेस का दावा है कि बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़ेंगे पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं और युवाओं को बेहतर शिक्षा तथा नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और रोजगार के अवसरों को लेकर युवाओं में असंतोष है कांग्रेस इन मुद्दों को जन-जन तक पहुंचाने और सरकार को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा पार्टी में 'स्लीपर सेल' संबंधी दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को भीतर से कमजोर करने वाले लोगों की पहचान कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है उनके अनुसार कांग्रेस आत्ममंथन के साथ संगठनात्मक मजबूती पर भी काम कर रही है। वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार में जनप्रतिनिधियों की भी अनदेखी हो रही है।

नर्मदापुरम में अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 2 लाख से अधिक की शराब जब्त

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए बालागंज क्षेत्र के कई ठिकानों पर छापेमारी की जिला आबकारी अधिकारी डॉ. राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में नर्मदापुरम और इटारसी की संयुक्त टीम ने करीब दो लाख रुपये से अधिक मूल्य की देशी और विदेशी शराब जब्त की कार्रवाई के दौरान कुछ शराब की बोतलें जमीन में गाड़कर छिपाई गई थीं जिन्हें भी बरामद कर लिया गया। आबकारी विभाग की टीम सुबह करीब 7 बजे पांच वाहनों के साथ बालागंज पहुंची और संदिग्ध मकानों की तलाशी शुरू की जांच के दौरान संगीता बाई के मकान से देशी और अंग्रेजी शराब की करीब 30 पेटियां बरामद हुईं इसके अलावा एक अन्य मकान में जमीन के भीतर गड्ढा बनाकर शराब की बोतलें छिपाई गई थीं टीम ने खुदाई कर सभी बोतलों को जब्त कर लिया।

बैतूल में सड़क हादसे में किसान की मौत, पत्नी घायल भैंसदेही के पास अज्ञात बोलेरो ने मारी टक्कर दूसरी बाइक भी चपेट में आई

मीडिया ऑडीटर, बैतूल (निप्र)। बैतूल जिले के भैंसदेही थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक सड़क हादसे में किसान की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई। यह घटना झिरी गांव के पास उस समय हुई जब दंपती अपनी बाइक से पांच डोंगरी से गांव लौट रहे थे। पुलिस और परिजनों के अनुसार, खेड़ापुर निवासी 39 वर्षीय रंगराव दहीकर अपनी पत्नी भागीरथी के साथ बाइक पर थे। झिरी के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रंगराव के सीने में गंभीर चोटें आई और उनका पैर भी टूट गया, जबकि उनकी पत्नी भी घायल हो गई। राहगीरों ने तत्काल दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदेही पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान रंगराव दहीकर ने दम तोड़ दिया।

एक अन्य बाइक को भी टक्कर मारी: मृतक के पुत्र प्रकाश दहीकर ने बताया कि यह हादसा बोलेरो की टक्कर से हुआ था। उसी वाहन ने एक अन्य बाइक को भी टक्कर मारी थी। रंगराव खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटनाग्रस्त वाहन की तलाश शुरू कर दी है।जिले में एक अन्य घटना में, भड़ूस के पास मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में पहचान के लिए रखवा दिया है। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की जानकारी खंगाल रही है और मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। पहचान होने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में 2,548 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पदों पर होगी भर्तीआवेदन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तक

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर पोषण प्रबंधन को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2,548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा रही हैं।

स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता: भर्ती में स्थानीय पात्रताधारियों को प्राथमिकता मिलेगी। कुल रिक्तियों में से 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और 1,767 पद आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन पदों पर चयन के लिए पारदर्शिता और स्थानीय प्रतिनिधित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नियमों के मुताबिक, आवेदिका का उसी राजस्व ग्राम या शहरी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है, जहां का पद रिक्त है। किसी अन्य ग्राम या वार्ड की महिला इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। इससे स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता मिलने से मैदानी स्तर पर सेवाओं का कुशल संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन केवल 13 जुलाई तक स्वीकार होंगे: भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रहेगी। इसमें एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इच्छुक महिला अभ्यर्थी चयन पोर्टल (httpsÑ//chayan.mponline.gov.in) पर जाकर 1 जुलाई 2026 से अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है, जबकि भरे गए फॉर्म में किसी भी प्रकार के त्रुटि सुधार के लिए 15 जुलाई 2026 तक का समय दिया जाएगा। विभाग द्वारा स्पष्ट किया है कि केवल पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। किसी भी स्तर के कार्यालय में ऑफलाइन भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

न्यूनतम योग्यता हायर सेकण्डरी, आयु सीमा 18-35 वर्ष तय: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा के मापदंडों के अनुसार, दोनों ही पदों के लिए आवेदिकाओं का हायर सेकेंडरी अर्थात 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों या अशासकीय बोर्डों की अंकसूचियों को तभी मान्यता दी जाएगी जब वे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की समकक्षता सूची में शामिल हों। साथ ही 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आवेदिका की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना आवश्यक है, जिसकी पुष्टि के लिए 10वीं बोर्ड की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन के दौरान सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करने होंगे, जिसके लिए निर्धारित शुल्क 100 रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है।

रिक्त पदों की जिलेवार स्थिति: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के अनुसार जिलेवार स्थिति इस प्रकार है। आलीराजपुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 10 तथा आंगनवाड़ी सहायिका के 22 पद रिक्त हैं। इंदौर जिले में कार्यकर्ता के 20 एवं सहायिका के 43 पद रिक्त हैं। खंडवा जिले में कार्यकर्ता के 15 तथा सहायिका के 32 पद रिक्त हैं। खरगोन जिले में कार्यकर्ता के 34 एवं सहायिका के 40 पद रिक्त हैं। झाबुआ जिले में कार्यकर्ता के 21 तथा सहायिका के 23 पद रिक्त हैं। धार जिले में कार्यकर्ता के 30 एवं सहायिका के 82 पद रिक्त हैं। बड़वानी जिले में कार्यकर्ता के 14 तथा सहायिका के 44 पद रिक्त हैं। बुरहानपुर जिले में कार्यकर्ता के 7 एवं सहायिका के 25 पद रिक्त हैं। आगर मालवा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 6 तथा सहायिका के 25 पद रिक्त हैं। उज्जैन जिले में कार्यकर्ता के 31 एवं सहायिका के 45 पद रिक्त हैं। देवास जिले में कार्यकर्ता के 16 तथा सहायिका के 35 पद रिक्त हैं। नीमच जिले में कार्यकर्ता के 8 एवं सहायिका के 32 पद रिक्त हैं। मंदसौर जिले में कार्यकर्ता के 9 तथा सहायिका के 25 पद रिक्त हैं। रतलाम जिले में कार्यकर्ता के 31 एवं सहायिका के 62 पद रिक्त हैं। शाजापुर जिले में कार्यकर्ता के 8 तथा सहायिका के 22 पद रिक्त हैं। अशोकनगर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 5 तथा सहायिका के 15 पद रिक्त हैं। गुना जिले में कार्यकर्ता के 19 एवं सहायिका के 38 पद रिक्त हैं। ग्वालियर जिले में कार्यकर्ता के 15 तथा सहायिका के 39 पद रिक्त हैं। दतिया जिले में कार्यकर्ता के 16 एवं सहायिका के 26 पद रिक्त हैं। शिवपुरी जिले में कार्यकर्ता के 23 तथा सहायिका के 37 पद रिक्त हैं। भिंड जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 8 तथा सहायिका के 37 पद रिक्त हैं। मुरैना जिले में कार्यकर्ता के 8 एवं सहायिका के 18 पद रिक्त हैं। श्योपुर जिले में कार्यकर्ता के 16 तथा सहायिका के 37 पद रिक्त हैं। कटनी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 9 तथा सहायिका के 15 पद रिक्त हैं। छिंदवाड़ा जिले में कार्यकर्ता के 38 एवं सहायिका के 48 पद रिक्त हैं। जबलपुर जिले में कार्यकर्ता के 12 तथा सहायिका के 38 पद रिक्त हैं। डिंडौरी जिले में कार्यकर्ता के 14 एवं सहायिका के 42 पद रिक्त हैं। नरसिंहपुर जिले में कार्यकर्ता के 18 तथा सहायिका के 28 पद रिक्त हैं। पांढुर्णा जिले में कार्यकर्ता के 5 एवं सहायिका के 10 पद रिक्त हैं। बालाघाट जिले में कार्यकर्ता के 24 तथा सहायिका के 51 पद रिक्त हैं। मंडला जिले में कार्यकर्ता के 19 एवं सहायिका के 26 पद रिक्त हैं।

नर्मदापुरम में शराब बेचने वालों के ठिकानों पर दबिश जमीन में गाड़कर छिपाई थीं बोतलें, 2 लाख से ज्यादा की मिली

नर्मदापुरम मीडिया ऑडीटर, (निप्र)। नर्मदापुरम में प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। जिला आबकारी अधिकारी डॉ. राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में नर्मदापुरम और इटारसी की संयुक्त टीम ने शहर के बालागंज क्षेत्र में कई ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान एक मकान से देशी और अंग्रेजी शराब की 30 पेटियां जब्त की गई। वहीं, एक अन्य घर में जमीन के भीतर गाड़कर शराब की बोतलें छिपाई गई थीं। आबकारी विभाग की टीम शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे पांच वाहनों के साथ बालागंज पहुंची। अधिकारियों ने अवैध शराब बेचने वालों के घरों की तलाशी शुरू की। जांच के दौरान संगीता बाई के मकान से देशी और अंग्रेजी शराब की करीब 30 पेटियां बरामद हुई। इतनी बड़ी मात्रा में शराब मिलने पर आबकारी टीम भी हैरान रह गई।

जमीन में छिपाकर रखी थीं शराब की बोतलें: तलाशी के दौरान एक अन्य मकान में जमीन के अंदर गाड़कर शराब की बोतलें छिपाई गई थीं। टीम ने उन्हें भी जब्त कर लिया। जिला आबकारी अधिकारी डॉ. राजेश द्विवेदी ने बताया कि सर्चिंग अभियान जारी है। अंतिम कार्रवाई और जब्ती का पूरा ब्योरा तलाशी पूरी होने के बाद जारी किया जाएगा। इस कार्रवाई में सहायक आबकारी अधिकारी आर.पी. अहिरवार, अभिलाष पाठक, राहुल कुमार डोके सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

प्रतिबंध के बावजूद फल-फूल रहा अवैध कारोबार: नर्मदापुरम शहर में नर्मदा नदी से पांच किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। इसी कारण शहर में वैध शराब दुकानें संचालित नहीं होतीं। इसके बावजूद अवैध रूप से शराब की तस्करी और ब्लैक में बिक्री का कारोबार लगातार जारी है। पुलिस और आबकारी विभाग समय-समय पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन अवैध बिक्री पूरी तरह नहीं रुक पा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, लंबे समय बाद आबकारी विभाग ने इस स्तर पर घरों में घुसकर कार्रवाई की है। पिछले कुछ महीनों में विभाग मुख्य रूप से देशी शराब जब्त कर रहा था, लेकिन इस बार बड़ी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद हुई है। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों और तस्करों में हड़कंप मच गया है।

सीहोर में मानसून मेहरबान, 24 घंटे में सवा इंच बारिश जावर में सबसे ज्यादा 2.81 इंच वर्षा, लगातार बारिश से नदी-नाले उफने

सीहोर मीडिया ऑडीटर, (निप्र)। सीहोर। जिले में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मूसलाधार बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। भू-अभिलेख विभाग के अनुसार, 3 जुलाई को जिले में औसतन 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं, 1 जून से अब तक जिले में कुल 9.08 इंच औसत वर्षा हो चुकी है। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 2.81 इंच बारिश जावर क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई। इसके बाद आष्टा में 2.32 इंच और भैंरुदा में 2.20 इंच वर्षा हुई। इसके अलावा श्यामपुर में 1.18 इंच, इछावर में 0.87 इंच, रेहटी में 0.65 इंच और जिला मुख्यालय सीहोर में 0.35 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं बुधनी में बारिश नहीं हुई।

पिछले साल से बेहतर शुरुआत: आंकड़ों के अनुसार, इस बार मानसून की शुरुआत पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही है। गत वर्ष 3 जुलाई तक जिले में औसतन केवल 0.16 इंच बारिश दर्ज हुई थी, जबकि इस वर्ष इसी अवधि में 1.25 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सीजन की कुल वर्षा भी पिछले साल से अधिक रही है। वर्ष 2025 में 3 जुलाई तक जिले में 8.74 इंच बारिश हुई थी, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 9.08 इंच पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर हुई यह बारिश खरीफ फसलों की बुवाई और शुरुआती बढ़वार के लिए लाभदायक मानी जा रही है।

शहडोल में तेज बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी उमस से राहत, बिजली गुल

मीडिया ऑडीटर, शहडोल(निप्र)। शहडोल जिले में शुक्रवार दोपहर बाद हुई तेज बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, लेकिन शहर के कई निचले इलाकों और मुख्य सड़कों पर जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने मानसून के सक्रिय रहने के कारण अगले 24 घंटे तक जिले में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है।

सड़कों पर बहा नालियों का पानी: देर शाम तक चली इस बारिश के कारण शहर की कॉलोनियों, बाजारों और मुख्य मार्गों पर पानी जमा हो गया। कई जगहों पर नालियों का पानी सड़कों पर बहने से राहगीरों और वाहन चालकों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

धान की फसलों को मिलेगा फायदा: ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। धान और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई कर चुके किसानों के मुताबिक यह पानी फसलों के लिए अमृत समान है। वहीं, जिन खेतों में अभी बुवाई नहीं हुई है, वहां भी नमी आने से खेती के काम में तेजी आएगी।

कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप: बारिश के दौरान जहां एक तरफ लोगों ने मौसम का आनंद लिया और दुकानों पर भीड़ दिखी, वहीं दूसरी तरफ जलभराव और हवाओं के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

नदी-नालों से दूर रहने की अपील: स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। तेज बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहें। इसके साथ ही नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

रायसेन में हरियाली बढ़ाने की सामूहिक शपथ छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण किया

मीडिया ऑडीटर,रायसेन (निप्र)। रायसेन के सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को इको क्लब द्वारा दो चरणों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। इस दौरान विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

अभियान का पहला चरण 29 जून 2026 को आयोजित किया गया। इसमें कक्षा तीसरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों ने विद्यालय परिसर में पौधे लगाए और पर्यावरणीय संतुलन, प्रदूषण नियंत्रण तथा वृक्षों के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरा चरण 2 जुलाई शुरू हुआ है, जिसमें कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस दौरान फूलदार, फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पौधों की नियमित देखभाल, उनके संरक्षण और सतत विकास के लिए वनीकरण के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। विद्यालय के प्राचार्य ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल के लिए प्रेरित किया। अभियान का समापन पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की सामूहिक शपथ के साथ हुआ। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि यह पहल विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है।

खजुराहो में तीन दिन में 4.6 मिमी बारिश दर्ज मानसून ने बढ़ाई प्राकृतिक खूबसूरती

मीडिया ऑडीटर, खजुराहो (निप्र)। मध्यप्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी है, जिससे क्षेत्र में ठंडक महसूस की जा रही है। गुरुवार दोपहर से खजुराहो में शुरू हुई बारिश ने उमस से राहत दिलाई है। बीते 24 घंटों के दौरान शहर में 4.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद, अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बारिश के कारण खजुराहो की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ गई है। इसका लाभ पर्यटकों को मिल रहा है, जिन्हें अब कड़ी धूप और गर्मी से राहत मिली है। सैलानी अब बिना किसी परेशानी के ऐतिहासिक मंदिरों का भ्रमण कर पा रहे हैं।

बारिश का दौर जारी रहने की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी बारिश का यह दौर जारी रहने की संभावना है। जून में औसत से कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने जुलाई महीने में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। सांख्यिकीय रुझानों के अनुसार, मानसून की कुल बारिश का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इसी महीने होने की संभावना है। वर्तमान में खजुराहो का मौसम पर्यटकों के लिए अनुकूल बना हुआ है। इस मानसून सीजन में अच्छी बारिश से क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है।

रायसेन में मानसून सुस्त, अब तक 5.59 इंच बारिश

पिछले साल से 4.41 इंच कम, 2.80 लाख हेक्टेयर धान रोपाई अटकी

मीडिया ऑडीटर,रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में मानसून की धीमी रफ्तार के कारण खरीफ की प्रमुख फसल धान पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। 1 जून से 2 जुलाई 2026 तक जिले में औसतन 142 मिमी (लगभग 5.59 इंच) बारिश दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 253.9 मिमी (लगभग 10.00 इंच) वर्षा से 111.9 मिमी (4.41 इंच) कम है। बारिश की इस कमी के कारण जिले के 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई रुक गई है। किसानों की नर्सरियों में धान की पौध पूरी तरह तैयार है, लेकिन खेतों में पर्याप्त पानी न होने से रोपाई शुरू नहीं हो पा रही है। किसान अब लगातार तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि खेतों में पानी भर सके और रोपाई का काम गति पकड़ सके। इस वर्ष जिले में खरीफ सीजन के लिए 4.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

धान के अलावा, बेगमगंज और गैरतगंज क्षेत्रों में कुछ किसानों ने मिट्टी की नमी का लाभ उठाकर लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी कर दी है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. स्वप्निल दुबे के अनुसार, धान की रोपाई जुलाई और अगस्त तक की जा सकती है। हालांकि, रोपाई में देरी होने पर फसल की कटाई भी देर से होगी। उन्होंने यह भी सलाह दी कि यदि मानसून सामान्य से कम रहता है, तो किसान कम पानी में तैयार होने वाली वैकल्पिक फसलों पर भी विचार करें।

इटारसी में 50 हजार के अवैध पटाखे जब्त थाने के सामने पुलिया के नीचे ऑटो से हो रही थी सप्लाई

मीडिया ऑडीटर,इटारसी (निप्र)। इटारसी पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखों के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 50 हजार रुपये के पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने पटाखों के साथ एक ऑटो भी जब्त किया है। जब्त किए गए पटाखों और ऑटो की कुल कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई 2 जुलाई की रात करीब 8:05 बजे थाना इटारसी के सामने पुलिया के नीचे की गई। पुलिस ने ललित चौधरी (33) और मुकेश कहार (28), दोनों निवासी गोंडी मोहल्ला, पुरानी इटारसी, के कब्जे से पटाखे बरामद किए। जांच के दौरान दोनों आरोपियों के पास पटाखों के भंडारण या परिवहन का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला।

शिवकाशी से लाए गए थे पटाखे: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जब्त किए गए पटाखे शिवकाशी से लाए गए थे। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पटाखों से जुड़े कोई वैध दस्तावेज भी पेश नहीं किए। जब्त पटाखों की कीमत करीब 50 हजार रुपये और ऑटो की कीमत करीब 2.50 लाख रुपये आंकी गई है।

सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 572/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 288 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उप निरीक्षक विपिन पाल ने की। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि बिना लाइसेंस लाए गए इन पटाखों की सप्लाई कहां की जानी थी और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोग कौन हैं। मामले की जांच जारी है।

सोसायटी का निरीक्षण, ई-टोकन से उर्वरक वितरण के दिए निर्देश; किसानों को वितरित किया उन्नत उड़द बीज

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। खरीफ वर्ष 2026 की तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा जिले में लगातार क्षेत्रीय भ्रमण, सोसायटी निरीक्षण तथा किसानों के बीच उन्नत बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपसंचालक कृषि श्री सचिन जैन ने गुरुवार को विकासखंड नटेरन के ग्राम एंचदा स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (सोसायटी) का निरीक्षण कर उर्वरक वितरण व्यवस्था का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने सोसायटी में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक एवं गोदाम की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने समिति प्रबंधक को निर्देश दिए कि किसानों को उर्वरक का वितरण केवल ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जाए तथा वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुव्यवस्थित रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को अनावश्यक परेशानी या प्रतीक्षा का सामना नहीं करना पड़े तथा सभी पात्र किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए।इसी क्रम में ग्राम आमखेड़ा कालू में कृषि विभाग द्वारा आईटीसी ई-चौपाल के सहयोग से उड़द मिनीकिट बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जगदीश गुर्जर ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उड़द बीज वितरित किए। इस अवसर पर क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी श्री राघवेंद्र अहिरवार, आईटीसी के श्री मनोज शर्मा, जिला पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, जनपद सदस्य एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि खरीफ सीजन की समय पर बुवाई सुनिश्चित करने तथा उड़द की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे उत्पादन में वृद्धि होने के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत कृषि तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी गई।

रोनाल्डो के नाम बड़ी उपलब्धि

नॉकआउट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने

नई दिल्ली,एजेसीं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर एक शानदार गोल दागा। इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का नॉकआउट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने 41 साल और 147 दिन की उम्र में यह मुकाबला खेला। इसके साथ ही रोनाल्डो नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले भी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। उन्होंने पूर्व खिलाड़ी पेपे का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 39 साल और 283 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। रोनाल्डो के अलावा, पुर्तगाल की ओर से गोंजालो रामोस ने निर्णायक गोल किया। क्रोएशिया के खिलाफ मिली जीत के साथ ही पुर्तगाल ने राउंड ऑफ 16 का टिकट हासिल कर लिया है। मुकाबले के पहले हाफ में पुर्तगाल और क्रोएशिया की ओर से कोई भी गोल नहीं हुआ। दोनों टीमों के डिफेंस ने शुरुआती 45 मिनटों में जबरदस्त खेल दिखाया। हालांकि, दूसरे हाफ के आगाज के साथ ही इवान पेरिसिच ने क्रोएशिया को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि, इस बढ़त को पुर्तगाल ने ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दिया। रोनाल्डो ने पेनल्टी के रूप में मिले शानदार मौके को भुनाते हुए बेहतरीन गोल दागा और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

इसके बाद इंजरी टाइम में राफेल लियाओ के बेहतरीन पास पर रामोस ने पुर्तगाल की तरफ से दूसरा गोल करते हुए टीम की जीत पर मुहर लगा दी। अतिरिक्त समय में क्रोएशिया की ओर से मारियो पासालिक ने गोल किया, लेकिन मारियो के ऑफसाइड होने की वजह से गोल को अमान्य करार दे दिया गया और क्रोएशिया का जश्न जल्द ही दुख में तब्दील हो गया। यह क्रोएशिया के दिग्गज खिलाड़ी लुका मॉड्रिक का आखिरी विश्व कप मुकाबला भी रहा। मैच के बाद रोनाल्डो मॉड्रिक से गले मिलते हुए भी नजर आए। पुर्तगाल ने जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं, हार के साथ क्रोएशिया का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है।

जीत के बाद पुर्तगाल टीम ने दी डिओगो जोटा को भावुक श्रद्धांजलि

रोनाल्डो ने पहनी 21 नंबर की जर्सी

टोरंटो ,एजेसीं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्रोएशिया पर 2-1 की जीत के बाद पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी टीम ने अपने पूर्व साथी डिओगो जोटा को भावुक श्रद्धांजलि दी। जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के एक साल पूरा होने पर पुर्तगाल टीम ने अपने पूर्व खिलाड़ी को याद किया। मैच के बाद रोनाल्डो ने डिओगो जोटा की नंबर 21 जर्सी पहनी और भावुक होकर आसमान की ओर इशारा किया। उनकी आंखों में आंसू थे और यह दृश्य खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला था। रोनाल्डो ने बाद में 'फॉक्स' के साथ बातचीत करते हुए बताया कि टीम को मैच से पहले ही इस तारीख के महत्व का एहसास था और यह दिन उनके लिए सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था। उन्होंने कहा कि यह बहुत खास और भावनात्मक पल था, क्योंकि टीम ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि एक ऐसे साथी की याद में जीत हासिल की जिसे वे बहुत प्यार करते थे। रोनाल्डो ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि जोटा हमेशा उनके साथ मौजूद हैं और टीम ने उन्हें सबसे अच्छे तरीके से श्रद्धांजलि दी है।

श्रीलंका दौरे पर 15 से 27 अगस्त के बीच दो टेस्ट मैच खेलेगा भारत

कोलंबो ,एजेसीं। भारत अगस्त 2026 में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-2027 चक्र का हिस्सा होगी। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त के बीच गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होगा। दोनों मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे। भारत और श्रीलंका के लिए यह दो मुकाबलों की सीरीज बेहद अहम है। दोनों टीमें डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में ऊपर चढ़ना चाहती हैं। मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र की प्वाइंट्स टेबल में, शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 9 मुकाबलों के बाद 48.15 के प्वाइंट्स प्रतिशत (पीसीटी) के साथ पांचवें स्थान पर है। वहीं, श्रीलंका 44.44 के पीसीटी के साथ छठे पायदान पर है। इस दो मुकाबलों की सीरीज में जीत किसी भी टीम को शीर्ष-2 में जगह बनाने और फाइनल में पहुंचने की कोशिश में बहुत काफी मदद करेगी। भारत ने पिछली बार साल 2017 में श्रीलंकाई सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेली थी। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने उस सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) की शुरुआत 17 जुलाई को होगी। इस टूर्नामेंट का समापन 8 अगस्त को होगा। इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने अपने कार्यक्रम में भारत और श्रीलंका के बीच प्रस्तावित तीन मैचों की टी20 सीरीज का कोई उल्लेख नहीं किया। इस सीरीज का प्रस्ताव शुरू में चक्रवात 'डिटवाह' के बाद द्वीप देश में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए फंड जुटाने के मकसद से दिया गया था। यह टी20 सीरीज मूल रूप से द्वीपीय देश में 'दितवाह चक्रवात' के बाद राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई थी। फिलहाल, ध्रुव जुरेल की कप्तानी वाली भारत-ए टीम गाले में दो मुकाबलों के रेड-बॉल शैडो टूर के लिए श्रीलंका में है। पहला मैच ड्रॉ होने के बाद, दूसरा चार दिवसीय मुकाबला गुरुवार से शुरू हो गया है।

एशियन गेम्स 2026 से पहले विजयी भारत फाउंडेशन से जुड़ीं ओलंपियन भवानी देवी

नई दिल्ली ,एजेसीं। सैबर तलवारबाज सी.ए. भवानी देवी एशियन गेम्स 2026 से पहले विजयी भारत फाउंडेशन (वीबीएफ) में शामिल हो गई हैं। वह वीबीएफ के उच्च-प्रदर्शन तलवारबाजी कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। भवानी देवी टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर (तलवारबाज) बनी थीं। भवानी का प्रदर्शन भी टूर्नामेंट में दमदार रहा था और उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भवानी ने अपने दमदार खेल के बूते गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।2022 में भी वह अपने इस प्रदर्शन को दोहराने में सफल रही थीं। इसके साथ ही उन्होंने 2023 में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भवानी ने महिलाओं के व्यक्तिगत इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 32 तक का सफर तय किया था। उन्होंने राउंड ऑफ 64 में ट्यूनीशिया की नादिया बेन अजीजी को एकतरफा मुकाबले में 15-3 से शिकस्त दी थी। हालांकि राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में भवानी को फ्रांस की मानोन ब्रुनेट के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। वीबीएफ में उनके शामिल होने से ग्लोबल फेंसिंग सर्किट का बेजोड अनुभव मिला है, जो वीबीएफ की टैलेंट पाइपलाइन में युवा फेंसर्स की भी मदद करेगा। इस एसोसिएशन के बारे में बात करते हुए भवानी ने कहा, 'मैं विजयी भारत फाउंडेशन और उनकी टीम से जुड़कर बहुत खुश हूं। मैं उनके खेल विकास कार्यक्रम, खासकर फेंसिंग के बारे में बहुत अच्छी खबरों को फॉलो कर रही हूं। मैं उनके सपोर्ट से आने वाले एक रोमांचक सीजन का इंतजार कर रही हूं।' भवानी ने हाल ही में दिल्ली में एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लिया था, जिसका हिस्सा विजयी भारत फाउंडेशन के सात फेंसर्स भी रहे थे। भवानी देवी के ओलंपिक तक का सफर तय करने के चलते भारत में तलवारबाजी के खेल को पहचान भी मिली। भवानी नेशनल लेवल पर 9 बार चैंपियन रह चुकी हैं। भवानी को साल 2021 में भारतीय सरकार द्वारा 'अर्जुन पुरस्कार' से भी नवाजा जा चुका है।

अभिषेक टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेजी से 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

डरहम ,एजेसीं। इंग्लैंड के खिलाफ बारिश के कारण यहां रद्द हुए पहले टी20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 59 रन की आतिशी पारी के दौरान एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम की। अभिषेक इस मैच में दो छक्के लगाते ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेजी से 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गये हैं। अभिषेक ने यह रिकार्ड केवल 785 गेंदों पर ही बना दिया। उन्होंने इस दौरान वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज एविन लुईस के रिकॉर्ड को तोड़ा। लुइस ने 789 गेंदों में अपने 100 छक्के लगाये थे। अभिषेक टी20 में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान पर आ गये हैं। दूसरे नंबर पर एविन लुईस (789 गेंद), फिन एलन (871 गेंद) के साथ ही तीसरे, टिम डेविड (931 गेंद) चौथे और कॉलिन मुनरो (963 गेंद) के साथ ही पांचवे नंबर रहे हैं।

अभिषेक ने अपनी इस पारी के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के सबसे तेजी से 100 टी20 छक्के लगाने के रिकार्ड को भी तोड़ दिया। सूर्यकुमार ने 1007 गेंदों का सामना किया था। अभिषेक ने यह कारनामा सूर्यकुमार से 222 गेंद पहले ही कर दिखाया। अब वे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले भारत के केवल पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में रोहित शर्मा (205 छक्के), सूर्यकुमार यादव (179 छक्के), हार्दिक पांड्या (126 छक्के) और विराट कोहली (124 छक्के) शामिल हैं, जिनके साथ अभिषेक ने 100 छक्के पूरे कर अपना नाम दर्ज कराया है।

श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, चार खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर

एंटीगुआ ,एजेसीं। : चोट और बीमारी के कारण श्रीलंका के लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो, रमेश मेंडिस और पथुम निसंका वेस्टइंडीज के साथ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गये है। श्रीलंका क्रिकेट (स्ष्ट) ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके चार खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि चोट और बीमारी के कारण लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो, रमेश मेंडिस और पथुम निसंका एंटीगुआ में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। दो टेस्ट मैचों की इस सीरीज में श्रीलंका अभी 1-0 से पीछे चल रहा है। निसंका पहले टेस्ट मैच में खेले थे, जिसमें वेस्टइंडीज ने एक पारी और 217 रनों से जीत हासिल की थी। निशान मदुष्का के साथ ओपनिंग करते हुए, उन्होंने 2 और 3 रन बनाए थे। स्ष्ट के अनुसार, पहले टेस्ट मैच के बाद निसंका 'लगातार कलाई में दर्द' की शिकायत हुई और उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी गई। इसके बाद सर्जरी के लिए वह मैच खत्म होने के दो दिन बाद ब्रिटेन रवाना हो गए।

कभी ट्रक ड्राइवर बनने का बना चुके थे मन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज ने बदला नसीब

नई दिल्ली,एजेसीं। हरभजन सिंह की गिनती उन महान ऑफ स्पिन गेंदबाजों के रूप में होती है, जिन्होंने भारत के लिए कई यादगार जीत में अहम भूमिका निभाई। टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक विकेट लेने वाले इस पहले भारतीय ऑफ स्पिनर को 'टर्बनेटर' नाम से भी जाना जाता है। 3 जुलाई 1980 को पंजाब के जालंधर में जन्मे हरभजन ने बड़े-बड़े धुरंधर बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया है। 'भज्जी' को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। घरेलू स्तर शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें मार्च 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू का मौका मिल गया। करीब डेढ़ साल तक भारत की तरफ से खेलने के बाद हरभजन सिंह को टीम से बाहर कर दिया गया था। अनिल कुंबले उस समय टीम इंडिया के स्टार स्पिनर थे, जिनके चोटिल होने के बाद भी भज्जी के बजाय दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिल रहा था, इससे वह काफी निराश थे।

इसी बीच साल 2000 में हरभजन सिंह के पिता का निधन हो गया। ऐसे में मां और 5 बहनों की जिम्मेदारी हरभजन सिंह के कंधों पर आ गई। एक ओर टीम में जगह न मिलना, तो दूसरी तरफ आर्थिक समस्या से जूझ रहे परिवार को देखते हुए भज्जी क्रिकेट छोड़ने पर विचार करने लगे थे।

एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 कप्तानों में भारत के शुभमन और गावस्कर भी शामिल

मुम्बई ,एजेसीं। क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप, टेस्ट मैच में कप्तानी और बल्लेबाजी का संतुलन बनाए रखना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन कुछ ऐसे दिग्गज कप्तान हुए हैं, जिन्होंने अपनी टीम की अगुवाई करते हुए बल्ले से भी रनों का अंबार लगाया और एक ही सीरीज में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, इसमें दो भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और शुभमन गिल भी शामिल हैं। इस सूची में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सर डॉन ब्रैडमैन का नाम आता है, जिनके नाम एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है।

सर डॉन ब्रैडमैन ने साल 1936-37 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की घरेलू सीरीज में यह महान रिकॉर्ड बनाया था। यह सीरीज उनके लिए कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों की अग्निपरीक्षा थी। ब्रैडमैन ने विरोधी गेंदबाजों को धवस्त करते हुए 9 पारियों में अविश्वसनीय 90.00 की औसत से 810 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 270 रन रहा। भले ही वे दो बार शून्य पर आउट हुए, लेकिन उनकी इस ऐतिहासिक कप्तानी पारी ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। टेस्ट इतिहास में किसी कप्तान द्वारा एक सीरीज में बनाए गए यह सबसे अधिक रन हैं।

आधुनिक क्रिकेट के उभरते सितारे और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी इसमें अपना नाम दर्ज कराया है। साल 2025 में इंग्लैंड दौरे पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान गिल ने कप्तानी के दबाव को बाहर करते हुए इंग्लैंड की तेज पिचों पर रनों की नई परिभाषा लिखी। 5 मैचों की 10 पारियों में उन्होंने 75.40 की औसत से 754 रन बनाए। इस सीरीज में शुभमन ने कमाल की निरंतरता दिखाते हुए 4 शानदार शतक लगाये, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा।

3 जुलाई को रायपुर में दौड़ेगा छत्तीसगढ़, होगा भव्य 'सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने और स्वस्थ एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के उद्देश्य से 3 जुलाई को राजधानी रायपुर में 'सहकार संकल्प दौड़' का भव्य आयोजन किया जाएगा।यह आयोजन 'सहकारिता की भावना के साथ, एक कदम समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर' थीम पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य लोगों में सहयोग, एकता, स्वास्थ्य और सामूहिक विकास का संदेश देना है।सुबह 6 बजे मरीन ड्राइव से होगी शुरुआत

दौड़ में पुरुष और महिला वर्ग के प्रतिभागियों के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इससे नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।सहकारिता और स्वस्थ जीवन का संदेशसहकार संकल्प दौड़ केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि जनजागरण का अभियान है। इसके माध्यम से सहकारिता को मजबूत बनाने, समाज में सहयोग की भावना विकसित करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जाएगा।इस आयोजन का उद्देश्य 'सहकारिता से समृद्धि ', 'साथ चलें, साथ बढ़ें' और 'स्वस्थ समाज, समृद्ध प्रदेश' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है।अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपीलछत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है। विभाग का मानना है कि जनभागीदारी से ही सहकारिता का अभियान और अधिक मजबूत होगा तथा समृद्ध और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प साकार होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा सख्त और सतत अभियान चलाया जा रहा है। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभिन्न जिलों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रेत, पत्थर, मिट्टी एवं गिट्टी के उत्खनन और परिवहन में संलिप्त वाहनों को जब्त किया गया है तथा नियमानुसार अर्थदंड एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासन का उद्देश्य प्रदेश के खनिज संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा अवैध उत्खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कइसी क्रम में राजनांदगांव जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के 52 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 18 लाख 95 हजार 600 रुपये का अर्थदंड वसूला गया है। इनमें अवैध उत्खनन के 9, परिवहन के 41 तथा भंडारण के 2 प्रकरण शामिल हैं। वहीं डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम आसरा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नदी में रेत उत्खनन प्रतिबंधित पाया गया तथा मौके पर कोई अवैध गतिविधि नहीं मिली। बालोद जिले के ग्राम कसही में अवैध पत्थर उत्खनन करते पाए जाने पर एक चेन माउंटेन (पीसी-130-7) मशीन को जब्त कर सील किया गया। संबंधित पक्ष वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

कर्राभौना में बंद हैंडपंप की हुई मरम्मत ग्रामीणों को मिली राहत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए ग्राम कर्राभौना में बंद पड़े हैंडपंप की मरम्मत कर उसे पुनः चालू कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों को पेयजल हेतु काफी राहत मिली है। विकासखंड बसना के ग्राम कर्राभौना निवासी श्री विजय कुमार चौहान ने सुशासन तिहार के दौरान ग्राम पंचायत कुम्हारी के आश्रित ग्राम कर्राभौना के वार्ड क्रमांक 06 में बंद पड़े हैंडपंप की मरम्मत हेतु आवेदन किया था। आवेदन प्राप्त होते ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। विभाग के तकनीकी दल द्वारा स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य किया गया तथा 09 जून 2026 को हैंडपंप की मरम्मत पूर्ण कर उसे पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। इससे वार्ड के ग्रामीणों को पुनः स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनो के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए प्रशासन एवं संबंधित विभाग निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे आमजन को उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान उपलब्ध कराया जा सके।

कोतबा में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य, सभी किसानों को मांग के अनुरूप मिल रहा ईंधन

रायपुर। राज्य सरकार प्रदेश में पेट्रोल-डिजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि जिलों में पेट्रोल एवं डिजल की पर्याप्त मात्रा में किसी प्रकार की अपवाहों पर ध्यान न दें। इसी कड़ी में जशपुर जिले के कोतबा क्षेत्र में डीजल आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है।जिला प्रशासन जशपुर के खाद्य अधिकारियों ने बताया कि कोतबा एवं आसपास के क्षेत्र में कुल 4 पेट्रोल पंप संचालित हैं। 23 जून को इनमें से 2 पेट्रोल पंपों पर डीजल समाप्त (ड्राई) हो गया था, एक पेट्रोल पंप में केवल रिजर्व स्टॉक उपलब्ध था तथा एक पेट्रोल पंप पर डीजल उपलब्ध होने के कारण ट्रैक्टरों की कतार लग गई थी।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने पुल निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण कर हर महीने प्रगति की समीक्षा के दिए निर्देश

नए कार्यों के प्राक्कलन 31 जुलाई तक भेजने कहा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों, मैदानी अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक लेकर प्रदेश में निर्माणाधीन पुलों, फ्लाई-ओवर्स और रेलवे ओवर-ब्रिजेस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिरपुर भवन स्थित सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता कार्यालय में आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण कर हर महीने प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित माइलस्टोन्स के अनुसार हर कार्य की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों पर कड़ी निगरानी रखते हुए कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने राज्य में निर्माणाधीन सभी पुलों की प्रगति की संभागवार और वर्षवार समीक्षा की। उन्होंने बस्तर में आरसीपीएलडब्लूए (RCPLWA) के अंतर्गत प्रगतिरत पुलों के कार्य हर हाल में दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलों, फ्लाई-ओवर्स और रेलवे ओवर-ब्रिजेस के निर्माण के लिए प्रत्येक चरण और प्रक्रिया को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के लिए मुख्य अभियंता को एसओपी बनाने को कहा। उन्होंने इनका कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित करने को कहा।विभागीय सचिव ने पुलों के निर्माण के दौरान कार्यस्थलों पर सुरक्षा के सभी मानकों का पूरा ध्यान रखने को कहा, जिससे की जान-माल की कोई हानि न हो। उन्होंने पुलों, फ्लाई-ओवर्स और रेलवे ओवर-ब्रिजेस के निर्माण में सड़क सुरक्षा के सभी मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को फील्ड में कार्यों का बारीकी से निरीक्षण कर ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के नियमित भुगतान करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों को हर महीने भुगतान करने को कहा। श्री बंसल ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 और पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के नए कार्यों की प्राथमिकता तय कर उनके प्राक्कलन 31 जुलाई तक भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने पहुंचविहीन गांवों तक बारहमासी कनेक्टीविटी के लिए पुलों के प्रस्ताव के साथ ही द्रुतगामी सड़कों में भी जहां पुलों की जरूरत है, उनके भी प्रस्ताव प्राथमिकता सूची में शामिल कर भेजने को कहा। उन्होंने कलेक्टरों के साथ समन्वय कर ब्लॉस्टिंग की अनुमति, भू-अर्जन, वन व्यपवर्तन, पेड़ कटाई तथा स्थल विवाद के लंबित मामलों का तेजी से निराकरण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इनका निराकरण नहीं होने की स्थिति में उच्च कार्यालयों को अवगत कराने को कहा, ताकि उच्च स्तर पर इनका समाधान निकाला जा सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जवाबदेही से काम करते हुए निर्माण सामग्री और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में पुलों के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने भारत सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर सभी पुलों की जानकारी 10 जुलाई तक अपलोड करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री एस.के. कोरी और अधीक्षण अभियंता श्री डी.के. माहेश्वरी सहित सभी मंडलों के अधीक्षण अभियंता, सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता तथा सभी उप संभागों के अनुविभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

स्काई-वॉक के संचालन-संधारण की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

श्री बंसल ने रायपुर में निर्माणाधीन स्काई-वॉक के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इसके संचालन और संधारण की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके चालू होने के बाद साफ-सफाई, रखरखाव और बिजली आपूर्ति की स्थायी और पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने इसके हैंड-ओवर के लिए नगर निगम से चर्चा करने के भी निर्देश दिए।बैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्काई-वॉक का काम इस साल दिसम्बर तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। लोगों के चढ़ने-उतरने के लिए 1.2 किमी लंबाई के इस स्काई-वॉक में 9 एस्केलेटर्स और 4 लिफ्ट भी लगाए जाएंगे।

ठेकेदारों की बैठक लेकर समस्याओं की ली जानकारी, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री बंसल ने पुलों का निर्माण कर रहे ठेकेदारों की बैठक लेकर कार्य एवं कार्यस्थलों पर आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही गुणवत्ता और समय पर कार्य पूर्णता में कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने, लोगों के बारहमासी आवागमन और माल परिवहन की दृष्टि से पुलों के निर्माण बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। निर्धारित समयावधि में अच्छा काम होना चाहिए।

125 दिनों के रोजगार से बढ़ी उम्मीदें: विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन बना ग्रामीणों का नया संबल

रोजगार अवधि बढ़ने एवं मजदूरी में वृद्धि से ग्रामीण परिवारों को मिलेगा आर्थिक सशक्तिकरण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और समग्र विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन से गांवों में नई उम्मीद जगी है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। योजना के तहत अब प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की गारंटी दी जाएगी। साथ ही मजदूरी दर में भी वृद्धि की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में इजाफा होगा। मुंगेली जिले के ग्राम लिम्हा की सुनीता साहू ने योजना के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रोजगार के दिनों में वृद्धि ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत है। पहले 100 दिनों तक ही रोजगार उपलब्ध होता था, लेकिन अब अतिरिक्त दिनों के रोजगार से परिवार की आय बढ़ेगी और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई मजदूरी और अतिरिक्त रोजगार के अवसर से अब परिवार को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इससे बच्चों की शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और अन्य खर्चों को पूरा करने में भी सहूलियत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब गांव में ही अधिक समय तक रोजगार मिलने से बाहर पलायन की आवश्यकता भी कम होगी। सुनीता साहू ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीणों के लिए केवल रोजगार की योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन का माध्यम है। इससे गांवों में जल

संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आधारभूत संरचना निर्माण तथा स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय ग्रामीण परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीएम हेल्पलाइन बनी आमजन के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण की दिशा में प्रदेशभर में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। शासन की जनहितैषी पहल के तहत आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे लोगों को शीघ्र राहत मिल रही है।इसी क्रम में बलरामपुर जिले के विकासखंड बलरामपुर अंतर्गत ग्राम रनहत एवं मकरो में खराब ट्रांसफार्मरों के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने संबंधी शिकायत श्री रामकृष्ण मिश्रा द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होते ही विद्युत विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी दल को तत्काल मौके पर भेजा। आवश्यक परीक्षण एवं मरम्मत कार्य पूर्ण कर दोनों गांवों के खराब ट्रांसफार्मरों को सुधारते हुए विद्युत आपूर्ति पुनः सुचारु कर दी गई।विद्युत आपूर्ति बहाल होने से ग्राम रनहत एवं

मकरो के ग्रामीणों को निर्बाध बिजली सुविधा मिलने लगी, जिससे दैनिक जीवन एवं अन्य गतिविधियों में आ रही कठिनाइयों का समाधान हुआ। शिकायत के त्वरित निराकरण पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी एवं भरोसेमंद मंच बताया।मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों के निरंतर और समयबद्ध निराकरण से शासन की पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली सुदृढ़ हो रही है तथा नागरिकों का प्रशासन के प्रति विश्वास भी लगातार बढ़ रहा है।

वन प्रबंधन समितियां को मत्स्य पालन से बनाया जा रहा आत्मनिर्भर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन और वन प्रबंधन समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा वनमंडल के गीदम परिक्षेत्र की कासोली वन प्रबंधन समिति ने मत्स्य पालन के माध्यम से आय बढ़ाने की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है।

400 किलोग्राम मछली का उत्पादन कर करीब 80 हजार रुपए की आय

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कासोली ग्राम के कक्ष क्रमांक 1338 में तालाब का निर्माण किया गया।

बीजापुर के मत्स्य पालन केंद्र को बनाया जाएगा प्रशिक्षण केंद्र

किसानों को मिलेगा आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण: कृषि मंत्री रामविचार नेताम

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन एवं पशुधन विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बीजापुर जिले के मत्स्य पालन केंद्र का निरीक्षण कर इसे भविष्य में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र (ट्रेनिंग सेंटर) के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में आसपास के किसानों को मत्स्य पालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार और आजीविका से जोड़ा जाएगा, जिससे जिले में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।मंत्री श्री रामविचार

नेताम ने हैचरी में संचालित मत्स्य उत्पादन गतिविधियों का अवलोकन किया और विभागीय अधिकारियों से केंद्र की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने लगभग 1.50 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इस केंद्र को जिले के किसानों के लिए आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण का मॉडल केंद्र बनाने पर जोर दिया। मंत्री श्री नेताम ने कार्यक्रम में मत्स्य पालकों को विभागीय योजनाओं के तहत सामग्री का वितरण करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को स्थायी आजीविका और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि बस्तर का प्राकृतिक वातावरण कृषि और मत्स्य पालन के लिए बेहद अनुकूल है। उन्होंने फल, फूल, कोदो, कुटकी, रागी जैसी फसलों के उत्पादन के साथ जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही स्व-सहायता समूहों को तालाबों की स्वीकृति देकर मत्स्य पालन और बकरी पालन जैसी गतिविधियों को विस्तार देने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बस्तर के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनी उम्मीद की किरण

सिर्फ एक सप्ताह में बना आयुष्मान कार्ड'

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इसी सुशासन की सोच को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 लगातार साकार कर रही है। मनेंद्रगढ़ निवासी अभिनव द्विवेदी की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, जहाँ एक शिकायत ने महज़ एक सप्ताह में उनकी चिंता को राहत में बदल दिया।काफी समय से आयुष्मान कार्ड नहीं बनने के कारण अभिनव द्विवेदी शासन की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद कार्ड जारी नहीं होने से वे परेशान थे। अंततः उन्होंने अपनी समस्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई और समाधान की उम्मीद जताई।शिकायत प्राप्त होते ही प्रकरण को स्वास्थ्य विभाग के पास भेजा गया। विभाग ने मामले को प्राथमिकता से लेते हुए आवश्यक परीक्षण एवं कार्रवाई की। लगातार मॉनिटरिंग और त्वरित प्रयासों के परिणामस्वरूप सिर्फ एक सप्ताह के भीतर अभिनव द्विवेदी का आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो गया।आयुष्मान कार्ड बनने के साथ ही अभिनव अब आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमारी की स्थिति में आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी।शिकायत के निराकरण के बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जब अभिनव से फीडबैक लिया गया, तो उन्होंने बताया कि उनकी समस्या का पूरी तरह समाधान हो चुका है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें इतनी शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वास्तव में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का भरोसेमंद माध्यम बन चुकी है।यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील समाधान का प्रभावी माध्यम है। जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सुशासन की भावना निरंतर सशक्त होती

सोशल मीडिया से मिली सीएम हेल्पलाइन 1076 की जानकारी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन 1076 की जानकारी मिलने के बाद बलौदाबाजार संजय कॉलोनी निवासी दिव्यांग दुर्गेश साहू ने नई ट्राई साइकिल प्रदान करने के लिए कॉल किया। इसके बाद 15 दिनों के भीतर उन्हें नई बैटरी संचालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध करा दी गई। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने आज दुर्गेश साहू को नई बैटरी संचालित ट्राइसाइकिल प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने दुर्गेश से उनका हाल-चाल जाना और ट्राइसाइकिल का अनुभव भी

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी
आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा